नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 195
दि. 19.04.2026,
रविवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

बंगाल का सियासी रण: 57 सीटों पर टिकेगी सत्ता की बाजी, कौन लिखेगा जीत की पटकथा?

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर निर्णायक मोड़ पर खड़ी है, जहां सत्ता का रास्ता इस बार बड़े जनसभाओं, तीखे भाषणों या चेहरे की चमक से नहीं, बल्कि उन 57 बेहद करीबी सीटों से होकर गुजरता दिख रहा है, जिन पर पिछली बार जीत-हार का अंतर बेहद मामूली था। यही वजह है कि 2026 का चुनाव केवल आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि रणनीति, धैर्य और जमीनी पकड़ की असली परीक्षा बन चुका है। 294 सीटों वाले इस राज्य में बहुमत के लिए 148 सीटों का आंकड़ा जरूरी है, लेकिन राजनीतिक जानकार मानते हैं कि असली चाबी उन सीटों में छिपी है जहां कुछ हजार या सैकड़ों वोटों ने पिछली बार पूरी तस्वीर बदल दी थी। 2021 के चुनावी नतीजों पर नजर डालें तो तृणमूल कांग्रेस ने 213 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत हासिल किया था, जबकि भारतीय जनता पार्टी 77 सीटों पर सिमट गई थी। पहली नजर में यह एकतरफा जीत लगती है, लेकिन जब इन आंकड़ों के भीतर झांकते हैं तो एक अलग ही कहानी सामने आती है। करीब 57 सीटों पर मुकाबला इतना करीबी था कि परिणाम आखिरी राउंड तक अटके रहे। दिनहाटा जैसी सीट पर तो जीत का अंतर महज 57 वोट रहा, जबकि करीब 10 सीटों पर यह अंतर 1000 वोट से भी कम था। इन सीटों पर टीएमसी और भाजपा के बीच लगभग बराबरी की टक्कर देखने को मिली थी, जो इस बार के चुनाव को और अधिक दिलचस्प बना रही है।

यही कारण है कि इस बार भाजपा ने अपनी पूरी रणनीति इन "क्लोज़ सीटों" पर केंद्रित कर दी है। पार्टी का मानना है कि अगर पिछली बार मामूली अंतर से हारी सीटों पर इस बार थोड़ी भी बढ़त मिल जाए, तो सत्ता का रास्ता खुल सकता है। उत्तर बंगाल और जंगलमहल जैसे क्षेत्रों में संगठन को मजबूत करना, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाना और स्थानीय मुद्दों को आक्रामक तरीके से उठाना भाजपा की रणनीति का अहम हिस्सा बन गया है। पार्टी यह मानकर चल रही है कि छोटे-छोटे स्विंग बड़े बदलाव ला सकते हैं और यही सीटें उसे बहुमत के करीब पहुंचा सकती हैं।

दूसरी ओर ममता बनर्जी की अगुवाई में टीएमसी ने भी इस चुनौती को भांपते हुए अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। पार्टी ने इस बार 74 मौजूदा विधायकों के टिकट काटकर साफ संकेत दिया है कि वह एंटी-इनकंबेंसी को हल्के में नहीं ले रही। खासकर उन सीटों पर यह कदम उठाया गया है जहां पिछली बार जीत का अंतर कम था या स्थानीय स्तर पर नाराजगी देखने को मिली थी। टीएमसी अब नए चेहरों, सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों और मजबूत संगठनात्मक ढांचे के जरिए इन सीटों पर अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश कर रही है।

राज्य के अलग-अलग क्षेत्रों में राजनीतिक समीकरण भी काफी हद तक अलग-अलग नजर आते हैं। उत्तर बंगाल के कूचबिहार, जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार जैसे इलाकों में भाजपा की पकड़ मजबूत मानी जाती है, लेकिन यहां भी कई सीटें ऐसी हैं जहां मुकाबला बेहद करीबी है। वहीं दक्षिण बंगाल—हावड़ा, हुगली, नदिया और उत्तर 24 परगना—में टीएमसी का दबदबा जरूर है, लेकिन यहां भी भाजपा ने चुनौती पेश की है। जंगलमहल के इलाके—पुरुलिया, बांकुड़ा और झाड़ग्राम—तो ऐसे हैं जहां हर चुनाव में नतीजे बदलते रहते हैं और छोटे अंतर बड़े राजनीतिक संदेश दे जाते हैं। इस चुनाव की एक दिलचस्प तस्वीर यह भी है कि जहां एक ओर कुछ सीटों पर लाखों वोटों का अंतर देखने को मिलता है, वहीं दूसरी ओर कई सीटों पर मुकाबला इतना नाजुक होता है कि हर वोट की अहमियत बढ़ जाती है। यही विरोधाभास बंगाल की राजनीति को अनोखा बनाता है—कहीं एकतरफा लहर, तो कहीं कांटे की टक्कर। यही कारण है कि इस बार राजनीतिक दल बड़े अंतर वाली सीटों से ज्यादा उन सीटों पर ध्यान दे रहे हैं, जहां 2 से 5 प्रतिशत वोटों का झुकाव पूरी बाजी पलट सकता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि 2026 का चुनाव बड़े नारों या चेहरे की लोकप्रियता से ज्यादा सूक्ष्म रणनीतियों पर निर्भर करेगा। बूथ मैनेजमेंट, स्थानीय उम्मीदवार की छवि, जातीय और सामाजिक समीकरण, और सरकारी योजनाओं का प्रभाव—ये सभी कारक मिलकर नतीजों को तय करेंगे। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि इस बार बंगाल की सत्ता की पटकथा बड़े मंचों पर नहीं, बल्कि छोटे-छोटे बूथों और गली-मोहल्लों में लिखी जाएगी।

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भाजपा इन 57 सीटों पर सेंध लगाकर सत्ता के करीब पहुंच पाएगी, या फिर टीएमसी अपने संगठन और रणनीतिक बदलावों के दम पर एक बार फिर "खेला" कर जाएगी। जवाब जो भी हो, इतना तय है कि इस बार का चुनाव हर मायने में बेहद रोमांचक, अनिश्चित और निर्णायक होने वाला है—जहां हर वोट, हर सीट और हर रणनीति इतिहास लिखने की ताकत रखती है।

एआई से नहीं, उसके दुरुपयोग से है खतरा न्यायपालिका के लिए संतुलन का संदेश

बंगलूरू में आयोजित न्यायिक अधिकारियों के 22वें द्विवार्षिक राज्य-स्तरीय सम्मेलन में भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने जिस स्पष्टता और संतुलन के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) पर अपने विचार रखे, वह न केवल न्यायपालिका बल्कि पूरे समाज के लिए दिशा तय करने वाला संकेत है। तेजी से बदलते तकनीकी युग में जहां हर क्षेत्र डिजिटल बदलाव से गुजर रहा है, वहीं न्याय व्यवस्था जैसे संवेदनशील और मूल्य-आधारित संस्थान के लिए यह परिवर्तन और भी अधिक जिम्मेदारी लेकर आता है। ऐसे समय में मुख्य न्यायाधीश का यह कहना कि "एआई विकल्प नहीं, बल्कि सहयोगी है" एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में सामने आता है।

दरअसल, आज एआई का उपयोग केवल तकनीकी क्षेत्रों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन और न्याय जैसे क्षेत्रों में भी प्रवेश कर चुका है। न्यायपालिका में एआई के इस्तेमाल की संभावनाएं कई प्रकार की हैं—जैसे केस मैनेजमेंट, दस्तावेज़ों का विश्लेषण, लंबित मामलों की प्राथमिकता तय करना और कानूनी शोध को तेज करना। इन सभी क्षेत्रों में एआई समय और संसाधनों की बचत कर सकता है, जिससे न्याय प्रक्रिया अधिक कुशल बन सकती है। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है—क्या मशीनें इंसानी विवेक और नैतिकता की जगह ले सकती हैं? मुख्य न्यायाधीश ने इसी सवाल का जवाब देते हुए स्पष्ट किया कि न्याय केवल डेटा और तथ्यों का विश्लेषण नहीं है, बल्कि यह एक संवेदनशील और नैतिक प्रक्रिया है। इसमें संविधान की आत्मा, सामाजिक संदर्भ और मानवीय संवेदनाओं की गहरी भूमिका होती है। एआई इन पहलुओं को पूरी तरह समझने में सक्षम नहीं है। इसलिए इसे केवल एक सहायक उपकरण के रूप में ही देखा जाना चाहिए, न कि निर्णय लेने वाले के रूप में। उन्होंने न्यायिक अधिकारियों को यह भी सलाह दी कि एआई का उपयोग करते समय सतर्कता और विवेक बनाए रखें। जिस तरह एक जज किसी जटिल मामले में गहराई से विचार करता है, उसी तरह एआई के सुझावों को भी बिना सोचे-समझे स्वीकार नहीं करना चाहिए। यह दृष्टिकोण इसलिए जरूरी है क्योंकि एआई सिस्टम भी अंततः इंसानों द्वारा बनाए गए एल्गोरिद्म पर आधारित होते हैं, जिनमें त्रुटियों की संभावना बनी रहती है।

इस संदर्भ में मुख्य न्यायाधीश ने "हैलुसिनेशन" यानी एआई द्वारा उत्पन्न भ्रम की समस्या पर विशेष चिंता जताई। यह वह स्थिति होती है जब एआई गलत या काल्पनिक जानकारी को भी तथ्य के रूप में प्रस्तुत कर देता है। न्यायपालिका जैसे क्षेत्र में, जहां हर निर्णय का गहरा सामाजिक और कानूनी प्रभाव होता है, ऐसी गलतियां बेहद खतरनाक साबित हो सकती हैं। यदि किसी केस में एआई द्वारा दी गई गलत जानकारी पर भरोसा कर लिया जाए, तो न्याय का संतुलन बिगड़ सकता है। इसके अलावा, एआई के दुरुपयोग का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। मुख्य न्यायाधीश ने चेतावनी दी कि कुछ लोग एआई का इस्तेमाल भ्रामक याचिकाएं तैयार करने या सतही तौर पर आकर्षक लेकिन कानूनी रूप से कमजोर तर्क प्रस्तुत करने के लिए कर सकते हैं। इससे न्यायालयों पर पहले से मौजूद बोझ और बढ़ सकता है। ऐसे में न्यायिक अधिकारियों के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वे एआई से प्राप्त जानकारी की सत्यता की जांच करें और केवल विश्वसनीय तथ्यों पर ही निर्णय आधारित करें। हालांकि, इन चुनौतियों के बावजूद एआई के सकारात्मक पहलुओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यदि सही तरीके से उपयोग किया जाए, तो यह न्यायपालिका की कार्यक्षमता को कई गुना बढ़ा सकता है। भारत जैसे देश में जहां लाखों मामले लंबित हैं, वहां एआई केस मैनेजमेंट और डेटा एनालिसिस के जरिए न्याय प्रक्रिया को तेज करने में मदद कर सकता है। इससे न केवल न्याय मिलने की गति बढ़ेगी, बल्कि आम नागरिकों का न्याय व्यवस्था पर विश्वास भी मजबूत होगा। मुख्य न्यायाधीश का यह दृष्टिकोण तकनीक और मानवता के बीच संतुलन स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि तकनीक का उपयोग तभी सार्थक है जब वह मानव मूल्यों और संवेदनाओं के साथ तालमेल बिठाए। न्यायपालिका का मूल उद्देश्य केवल कानून लागू करना नहीं, बल्कि न्याय सुनिश्चित करना है—और यह कार्य केवल मशीनों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता।

केरल में सियासी हिंसा पर कड़ा प्रहार: थिमिरी बम कांड में 10 सीपीएम कार्यकर्ताओं को 25-25 साल की सजा

कन्नूर। केरल के उत्तरी जिले कन्नूर में वर्षों से simmer कर रही राजनीतिक हिंसा की आग पर न्यायपालिका ने ऐसा फैसला सुनाया है, जिसने न केवल दोषियों को सख्त सजा दी है बल्कि पूरे देश में यह संदेश भी गूंजा दिया है कि लोकतंत्र के नाम पर खून-खराबा अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 2011 के चर्चित थिमिरी बम हमला मामले में थलिपरम्बा की अदालत ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) के 10 कार्यकर्ताओं को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को 25-25 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने अपने फैसले में साफ शब्दों में कहा कि राजनीतिक विचारधाराओं की लड़ाई यदि हिंसा में बदलती है तो वह लोकतंत्र के मूल ढांचे पर हमला बन जाती है, और ऐसे कृत्यों को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता।

यह पूरा मामला वर्ष 2011 का है, जब कन्नूर जिले के अलाकोड क्षेत्र के पास थिमिरी में एक भयावह बम हमला हुआ था। उस समय इलाके में पहले से ही राजनीतिक तनाव चरम पर था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं को निशाना बनाकर किए गए इस हमले ने पूरे राज्य को हिला कर रख दिया था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हमलावरों ने अचानक बम फेंककर इलाके में दहशत फैला दी थी। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि लंबे समय से पनप रही दुश्मनी और बदले की भावना का परिणाम थी।

अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो तस्वीर पेश की, वह केरल की उस सियासी हकीकत को उजागर करती है, जहां विचारधारा की लड़ाई कई बार खून-खराबे तक पहुंच जाती है। सबूतों और गवाहों के आधार पर यह साबित किया गया कि हमला पूरी तरह से सुनियोजित था। आरोपियों ने पहले से रणनीति बनाई, लक्ष्य तय किया और फिर उसे अंजाम दिया। अदालत ने इस बात को विशेष रूप से रेखांकित किया कि यह केवल एक आपराधिक घटना नहीं थी, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ एक गंभीर हमला था।

फैसले के दौरान एडिशनल जिला एवं सत्र न्यायाधीश केएन प्रशांत ने बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी भी राजनीतिक विचारधारा या संगठन को यह अधिकार नहीं है कि वह अपने विरोधियों को हिंसा के जरिए खत्म करने की कोशिश करे। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी घटनाओं को कड़ी सजा नहीं दी गई, तो समाज में अराजकता का माहौल पैदा हो जाएगा और कानून का डर खत्म हो जाएगा।

इस मामले में 'उडुम्ब बिनु' के नाम से चर्चित टीवी बिनु समेत कुल 10 आरोपियों को दोषी पाया गया। अदालत ने सभी को 25-25 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई, जो अपने आप में एक बड़ा और सख्त दंड माना जाता है। हालांकि, फैसले में एक महत्वपूर्ण कानूनी पहलू भी सामने आया, जिसने सजा के व्यावहारिक असर को थोड़ा बदल दिया। अदालत ने निर्देश दिया कि 10 में से 9 दोषियों की सजा एक साथ चलेगी, जिसे कानूनी भाषा में 'समवर्ती सजा' कहा जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि भले ही कागजों पर सजा 25 साल की है, लेकिन वास्तविक रूप से उन्हें लगभग 10 साल जेल में बिताने होंगे।

यह फैसला सिर्फ एक मामले का अंत नहीं है, बल्कि केरल की उस राजनीतिक संस्कृति पर सवाल खड़ा करता है, जहां दशकों से वामपंथी और दक्षिणपंथी संगठनों के बीच हिंसक टकराव होते रहे हैं। कन्नूर खास तौर पर ऐसे संघर्षों का केंद्र रहा है, जहां कई परिवारों ने अपने प्रियजनों को इस सियासी हिंसा में खोया है। इस पृष्ठभूमि में अदालत का यह निर्णय एक चेतावनी की तरह देखा जा रहा है कि अब कानून का शिकंजा और कसने वाला है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले का प्रभाव आने वाले समय में दूरगामी हो सकता है। इससे न केवल राजनीतिक दलों को अपने कार्यकर्ताओं पर नियंत्रण रखने का संदेश मिलेगा, बल्कि आम लोगों में भी यह विश्वास मजबूत होगा कि न्याय व्यवस्था किसी भी प्रकार की हिंसा के खिलाफ निष्पक्ष और सख्त है। यह फैसला यह भी दर्शाता है कि अदालतें अब सिर्फ अपराध को दंडित करने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि समाज में एक संतुलन और भय का माहौल बनाए रखने की भूमिका भी निभा रही हैं।

आज जब देश के कई हिस्सों में राजनीतिक मतभेद तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में कन्नूर की यह घटना और उस पर आया यह फैसला एक आईना बनकर सामने आता है। यह याद दिलाता है कि लोकतंत्र की असली ताकत बहस और विचारों के आदान-प्रदान में है, न कि बम और बंदूक की भाषा में। अदालत ने अपने फैसले से यह स्पष्ट कर दिया है कि जो लोग इस सीमा को लांघेंगे, उनके लिए कानून के दरवाजे सख्ती से बंद नहीं, बल्कि और अधिक कठोर रूप में खुलेंगे।

होर्मुज पर फिर छाया युद्ध का साया: ईरान ने जलडमरूमध्य बंद कर अमेरिका को दी खुली चुनौती

तेहरान। पश्चिम एशिया एक बार फिर उस खतरनाक मोड़ पर खड़ा नजर आ रहा है, जहां से वैश्विक अर्थव्यवस्था, तेल आपूर्ति और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा सीधे प्रभावित हो सकती है। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक होर्मुज जलडमरूमध्य को ईरान ने एक बार फिर बंद करने का ऐलान कर दिया है, और इसके साथ ही अमेरिका पर युद्धविराम तोड़ने का गंभीर आरोप भी लगा दिया है। इस कदम ने न केवल खाड़ी क्षेत्र में तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है, बल्कि दुनिया भर के देशों को भी चिंता में डाल दिया है, क्योंकि वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है।

ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने साफ शब्दों में कहा है कि जब तक उसके बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकाबंदी जारी रहेगी, तब तक वह होर्मुज जलडमरूमध्य को खुला नहीं रखेगा। ईरान का आरोप है कि अमेरिका ने युद्धविराम की शर्तों का उल्लंघन करते हुए उसके समुद्री व्यापार को बाधित करना जारी रखा है और उसकी आड़ में जहाजों को रोकने तथा तलाशी लेने जैसी कार्रवाइयां की जा रही हैं, जिन्हें तेहरान ने "समुद्री डकैती" तक करार दिया है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि यह सिर्फ एक सैन्य प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि अपनी संप्रभुता और आर्थिक अधिकारों की रक्षा का कदम है।

इस पूरे घटनाक्रम ने अचानक मोड़ तब लिया जब एक दिन पहले ही ईरान ने घोषणा की थी कि वह होर्मुज जलडमरूमध्य को पूरी तरह खोल रहा है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने इसे क्षेत्रीय शांति की दिशा में एक सकारात्मक कदम बताया था और कहा था कि इजरायल और लेबनान के बीच दस दिन के युद्धविराम के बाद हालात सामान्य करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। उस समय ऐसा लगा था कि लंबे समय से चले आ रहे तनाव में कुछ नरमी आ सकती है, लेकिन अमेरिका के सख्त रुख ने इस उम्मीद को ज्यादा देर टिकने नहीं दिया।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया था कि भले ही जलडमरूमध्य खोला जाए, लेकिन ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी तब तक जारी रहेगी, जब तक तेहरान अपने परमाणु कार्यक्रम समेत विभिन्न मुद्दों पर वाशिंगटन के साथ व्यापक समझौता नहीं कर लेता। ट्रंप के इस बयान को ईरान ने सीधे तौर पर दबाव की राजनीति और वादाखिलाफी के रूप में लिया। उन्होंने यह भी चेतावनी दी थी कि यदि तय समयसीमा तक कोई समझौता नहीं हुआ, तो युद्धविराम को खत्म किया जा सकता है और सैन्य कार्रवाई दोबारा शुरू हो सकती है।

इस टकराव का सबसे बड़ा असर वैश्विक तेल बाजार पर पड़ने की आशंका है। होर्मुज जलडमरूमध्य वह संकीर्ण समुद्री मार्ग है, जहां से दुनिया के लगभग 20 प्रतिशत तेल का परिवहन होता है। इसके बंद होने का मतलब है तेल की कीमतों में तेज उछाल, आपूर्ति संकट और कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर सीधा दबाव। भारत जैसे ऊर्जा आयात पर निर्भर देशों के लिए यह स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक हो सकती है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह सिर्फ सैन्य या राजनीतिक टकराव नहीं, बल्कि एक बड़ी रणनीतिक शतरंज है, जिसमें हर चाल का असर वैश्विक स्तर पर पड़ रहा है। एक ओर ईरान अपने क्षेत्रीय प्रभाव और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए आक्रामक रुख अपना रहा है, तो दूसरी ओर अमेरिका अपने रणनीतिक दबाव को बनाए रखने के लिए पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा। इस बीच खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अन्य देश और अंतरराष्ट्रीय समुदाय स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन फिलहाल किसी ठोस समाधान के संकेत नजर नहीं आ रहे। तेजी से बदलते इस घटनाक्रम ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या दुनिया एक बड़े संघर्ष की ओर बढ़ रही है, या फिर कूटनीति आखिरी समय में कोई रास्ता निकाल लेगी। फिलहाल, होर्मुज के पानी में सिर्फ जहाजों की आवाजाही ही नहीं, बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता भी ठहरती हुई नजर आ रही है।

संपादकीय

महिला आरक्षण व परिसीमन विधेयक सिरे न चढ़े

जैसे कि पहले से कायस लगाए जा रहे थे, शुक्रवार को लोकसभा में संविधान में प्रस्तावित 131वां संशोधन बिल मतदान के बाद गिर गया। दरअसल, यह बिल देश में महिला आरक्षण कानून में संशोधन के लिए लाया गया था। राजनीतिक पंडित पहले ही कह रहे थे कि संविधान संशोधन के लिये जरूरी दो तिहाई बहुमत सरकार के पास नहीं है, जिससे बिल के पारित होने पर संशय था। वैसा ही हुआ और राजग सरकार दो तिहाई वोट हासिल करने में विफल रही। बिल के समर्थन में 298 और इसके विरोध में 230 वोट पड़े। आखिरकार सरकार की ओर से कहा गया कि अब दोनों बाकी प्रस्तावित संशोधन बिलों को आगे न बढ़ाने का निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि महिलाओं को 33 आरक्षण देने वाले कानून में संशोधन को लेकर बुलाए गए विशेष सत्र में पिछले कुछ दिनों से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गरमागरम बहस जारी थी। विपक्ष इस संशोधन में शामिल परिसीमन को लेकर सरकार की घेराबंदी कर रहा था। दरअसल, दक्षिण भारत के उन राज्यों में इसको लेकर खासा विरोध था जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण करके आर्थिक विकास को प्राथमिकता बनाया था। उनकी आशंका थी कि परिसीमन विधेयक के अस्तित्व में आने से संसद में इन राज्यों का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। विपक्ष में का आरोप है कि संसद का विशेष सत्र बुलाकर महिला आरक्षण संशोधन बिल को पारित करने का उपक्रम महज कुछ राज्यों में हो रहे चुनाव में बढ़त हासिल करने के लिये था। ताकि महिला वोटरों को लुभाया जा सके। विपक्ष ने संसद में जारी बहस के बीच कानून मंत्रालय द्वारा महिला आरक्षण अधिनियम 2023 को लागू करने के लिये अधिसूचना जारी करने पर भी सवाल उठाये। उल्लेखनीय है कि महिला आरक्षण कानून का उद्देश्य संसद और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिये 33 फीसदी आरक्षण लागू करने का प्रावधान था। मगर राजग सरकार ने प्रस्तावित 131वें संविधान बिल 2026 में सीटों में आरक्षण को परिसीमन के आधार पर लागू करने की बात कही थी।

दरअसल, विपक्ष इस संशोधन बिल की टाइमिंग और आरक्षण को परिसीमन के आधार पर लागू करने की शर्त पर सवाल उठाता रहा है। कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा गया कि 33 फीसदी आरक्षण को लोकसभा की मौजूदा सीटों के आधार पर ही लागू करना चाहिए। विपक्ष परिसीमन से उपजी विसंगतियों और दक्षिण के राज्यों की चिंताओं को तरजीह देने की बात करता रहा है। वहीं सत्ता पक्ष की दलील रही कि विपक्ष महिला आरक्षण का विरोध कर रहा है। बिल का मकसद महिला सशक्तीकरण ही है। जिसके लिये इसके लागू करने के तरीके का विरोध किया जा रहा है। सत्ता पक्ष की दलील थी कि परिसीमन संविधान सम्मत है और बढ़ती आबादी के बाद सीटों को तार्किक बनाये जाने की जरूरत है। इस बीच दोनों पक्षों की ओर से एससी-एसटी के हितों के पैरोकार होने की दलीलें भी दी गई। सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर उत्तर-दक्षिण का नैरेटिव गढ़ने का आरोप भी लगाया। साथ ही विपक्ष को महिलाओं के आक्रोश की कीमत चुकाने की भी चेतावनी दी। वहीं विपक्ष ने केंद्र पर देश का चुनावी नक्शा बदलने की कोशिश का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि ये संशोधन दलित व पिछड़े वर्गों के हित में नहीं है। सवाल इस बात को लेकर भी उठाये गए कि 2011 की जनगणना को आधार बनाकर परिसीमन करना कितना न्यायसंगत है। इसके लिये नये जनगणना के आंकड़े आने का इंतजार क्यों नहीं किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने परिसीमन को संघीय ढांचे को प्रभावित करने वाला बताया। उन्होंने महिला आरक्षण लागू करने को परिसीमन से जोड़ने की तार्किकता को लेकर भी सवाल उठाया। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को खारिज किया कि निर्णय प्रक्रिया किसी भी तरह किसी के साथ भेदभाव करेगी। उन्होंने कहा कि परिसीमन पहले के अनुपात के अनुसार ही किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 33 फीसदी महिलाओं को यहां आने दें और उन्हें निर्णय करने दें।

बिंदी Ban, हिजाब Allowed, Lenskart के वायरल डॉक्यूमेंट पर क्या विवाद चल रहा है?

> लेंस कार्ड की 27 पन्नों की गाइड बुक में तमाम ऐसे नियम है जिन्हें लेकर कंट्रोवर्सी हो रही है। वैसे लेंस कार्ड के सीईओ पीयूष बंसल ने इन नियमों को पुराना बताया है। लेकिन ट्रोल्स का कहना है कि गाइडलाइन पुरानी हो या फिर नई हो है तो आपकी ही। पहले जानेंगे कि किन नियमों को लेकर विवाद है और फिर जानेंगे कि पीयूष बंसल का क्या कहना है।

अभी टाटा कंसलटेंसी सर्विज यानी टीसीएस से जुड़ा विवाद पूरी तरह थमा भी नहीं था कि एक और बड़ी कंपनी को लेकर कंट्रोवर्सी सामने आने लगी है। इस बार मामला सिर्फ एक कंपनी तक सीमित नहीं है बल्कि उस सवाल का है जो हम सबके वर्क प्लेस से सीधे जुड़ा है। मामला है ड्रेस कोड पॉलिसी का। क्या एक कंपनी यह तय कर सकती है कि आप अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी कैसे दिखाएं? या अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को दिखाना जरूरी है भी? क्या ऑफिस में आपकी धार्मिक पहचान और उससे जुड़े पर्सनल बिलीफ आपकी अपनी चॉइस होगी या कंपनी की पॉलिसी उसे तय करेगी? तमाम विवाद चश्मे बनाने वाली पॉपुलर कंपनी लेंस कार्ड से जुड़ा है। क्या है लेंस कार्ड से जुड़ी कंट्रोवर्सी और क्यों हो रही है इसकी इतनी चर्चा? दरअसल, लेंस कार्ड की 27 पन्नों की गाइड बुक में तमाम ऐसे नियम है जिन्हें लेकर कंट्रोवर्सी हो रही है। वैसे लेंस कार्ड के सीईओ पीयूष बंसल ने इन नियमों को पुराना बताया है। लेकिन ट्रोल्स का कहना है कि गाइडलाइन पुरानी हो या फिर नई हो है तो आपकी ही। पहले जानेंगे कि किन नियमों को लेकर विवाद है और फिर जानेंगे कि पीयूष बंसल का क्या कहना है।

लेंसकार्ट स्टाफ यूनिफार्म एंड ग्रूमिंग गाइड पर एक्स यूजर ने उठाए सवाल

शुरुआत एक एक्स पोस्ट से हुई। 15 अप्रैल को शेफाली वैद नाम की एक्स यूजर ने लेंस कार्ड को टैग करते हुए कुछ फोटो शेयर की। इन तस्वीरों को लेंस कार्ट स्टाफ यूनिफार्म एंड ग्रूमिंग गाइड का हिस्सा बताया जा रहा है। तस्वीर में दिखाए गए नियम के हिसाब से कंपनी की वर्कर्स एक पर्टिकुलर लेंथ का हिजाब पहन सकती हैं। लेकिन किसी भी कलर

की बिंदी, स्टोन या फिर कलावा नहीं पहन सकती। सिंदूर को लेकर भी नियम बताया गया कि इसे मिनिमम लगाना है और इस तरह से लगाना है कि माथे पर नहीं आए। इस तरह के और भी कई सारे नियमों का जिक्र किया गया। इस फोटो को शेयर करते हुए यूजर ने लिखा मैं नियमों को कंफर्म कर रही हूं। पीयूष बंसल अपने वर्कर्स को यही बताते हैं कि हिजाब ओके है लेकिन बिंदी तिलक क्या कलावा ओके नहीं है। यह ऐसी कंपनी है जो हिंदू बहुल देश भारत में है। जिसके अधिकतर वर्कर्स और कस्टमर हिंदू हैं। आप इस पर क्या कहेंगे?

वायरल डॉक्यूमेंट में कई तरह के ड्रेस कोड निर्देश दिए गए थे। इसमें कहा गया था कि अगर कोई कर्मचारी पगड़ी पहनता है तो उसका रंग काला होना चाहिए। इसी तरह हिजाब पहनने की अनुमति थी लेकिन उसके लिए भी काले रंग की शर्त रखी गई थी। साथ ही यह भी कहा गया था कि हिजाब का कवरेज सीमित हो। वहीं स्टोर में बुर्का पहनने की अनुमति नहीं दी गई थी। विज़िबल टैटू से बचने की सलाह दी गई थी ताकि किसी की धार्मिक भावनाएं आहत ना हो। इसके अलावा मेहंदी लगाने पर भी रोक थी और अगर किसी खास मौके पर लगानी हो तो पहले से अनुमति लेनी होगी और वह भी सीमित समय के लिए। सबसे ज्यादा विवादित हिस्सा वो था जिसमें धार्मिक प्रतीकों को लेकर निर्देश दिए गए थे। जैसे कि तिलक, बिंदी या किसी भी तरह का धार्मिक स्टीकर पहनने की अनुमति नहीं थी।

हिंदू संस्कृति और परंपराओं को किया जा रहा टारगेट?

यह नियम लेंस कार्ट स्टाइल गाइड के पेज नंबर 11 में लिखा है। इस फोटो को शेयर करते हुए एक और यूजर ने लिखा, क्या सच में यह हिंदू बहुसंख्यक या सेकुलर देश है? हिंदुओं के साथ भेदभाव किया जाता है और अल्पसंख्यक मुसलमानों को वर्क प्लेस में अपनी धार्मिक पहचान का पालन करने की इजाजत दी जाती है। लेंस कार्ट यह रवैया हिंदू संस्कृति और परंपराओं को टारगेट कर रहा है। ऐसे ही और सारे कमेंट्स आए तो पीयूष बंसल ने जवाब भी दिया।

पीयूष ने लिखा कि हर साल नियमों में बदलाव होता है। हमारी कंपनी में अलग-अलग धर्म के हजारों लोग काम करते हैं। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। इसके आगे पीयूष ने जो लिखा हम शब्दशा बता देते हैं। पीयूष ने लिखा, मैंने देखा है कि लेंस कार्ड का गलत पॉलिसी डॉक्यूमेंट वायरल हो रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि यह डॉक्यूमेंट हमारे वर्तमान दिशा निर्देशों को नहीं दिखाता। हमारी पॉलिसी में धार्मिक अभिव्यक्ति पर कोई रोक नहीं है। इसमें बिंदी और तिलक भी शामिल है। हम नियमित रूप से अपने दिशा निर्देशों को रिव्यू करते रहते हैं। हमारी ग्रूमिंग पॉलिसी समय के साथ विकसित हुई है और इसके पुराने नियम आज हमारी पहचान को सही ढंग से नहीं दिखाते हैं। आपको जो कंफ्यूजन हुआ उसके लिए हम माफी चाहते हैं। एक कंपनी के रूप में हम लगातार सीखते और आगे बढ़ते हैं। हमारी भाषा या नीतियों में खामियों को दूर किया गया है और आगे भी किया जाता रहेगा। भारत में हमारे हजारों कर्मचारी जो हमारे स्टोर्स में अपने धर्म और संस्कृति को गर्व से दिखाते हैं। यही लेंस कार्ड है। लेंस कार्ड भारत में बना था भारतीयों द्वारा और भारतीयों के लिए। हमारे लोगों की हर परंपरा हमारी कंपनी की पहचान का हिस्सा है। मैं कभी भी इसे खतरे में नहीं पड़ने दूंगा।

यूजर ने पीयूष के जवाब पर क्रॉस क्वेश्चन किया। लिखा कि सॉरी, इस सफाई का कोई मतलब नहीं है। ये डॉक्यूमेंट फरवरी 2026 का है। अगर ये नियम आज की गाइडलाइन को नहीं दिखाते तो प्लीज नए वाले शेयर कर दीजिए। भले ही यह पुराना डॉक्यूमेंट हो तो उस समय भी इसे क्यों स्वीकार किया जाता था। हिजाब और पगड़ी की इजाजत थी लेकिन बिंदी, सिंदूर और कलावा की नहीं। इसके पीछे क्या लॉजिक था? अपने वकील से कहिए इस तरह का कमजोर स्पष्टीकरण तैयार करने के बजाय बेहतर तरीके से काम करें। इसके बाद इस खबर को रिकॉर्ड किए जाने तक पीयूष का कोई जवाब सामने नहीं आया।

प्रेरणा

जब एक निर्णय ने रच दिया साहित्य का स्वर्णिम इतिहास

मनुष्य के जीवन में ऐसे अनेक अवसर आते हैं, जब उसे अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने का निर्णय लेना होता है। यही वे क्षण होते हैं, जो उसकी पहचान गढ़ते हैं और यह तय करते हैं कि वह भीड़ का हिस्सा बनेगा या अपने लिए एक अलग मार्ग बनाएगा। इतिहास के पन्नों में झांकें तो पाएंगे कि हर महान व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा मोड़ अवश्य आया है, जहां उसने परिस्थितियों के आगे झुकने के बजाय उन्हें चुनौती दी। हिंदी साहित्य के अमर रचनाकार Munshi Premchand का जीवन भी इसी अडिग निश्चय और आत्मविश्वास का अद्भुत उदाहरण है, जिसने यह साबित कर दिया कि यदि मन में दृढ़ इच्छा हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता।

प्रेमचंद का प्रारंभिक जीवन संघर्षों और अभावों से भरा रहा, लेकिन उनके भीतर एक अदम्य जिज्ञासा और अभिव्यक्ति की तीव्र इच्छा थी। उन्होंने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत उर्दू भाषा से की और 'नवाब राय' के नाम से लेखन किया। उस समय हिंदी उनके लिए एक अनजानी भाषा थी, जिससे उनका कोई गहरा संबंध नहीं था। फिर भी वे अपने विचारों को समाज तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत रहे। उनके भीतर एक लेखक का आत्मविश्वास था, जो किसी भी भाषा की सीमा में बंधकर नहीं रहना चाहता था।

जब उनके उर्दू कहानी संग्रह 'सोज-ए-वतन' पर अंग्रेजी शासन ने प्रतिबंध लगा दिया, तब यह घटना उनके जीवन का निर्णायक मोड़ बन गई। यह केवल एक पुस्तक पर लगी रोक नहीं थी, बल्कि उनके विचारों की स्वतंत्रता पर लगा अंकुश था। ऐसे समय में अधिकांश लोग हताश होकर अपने कदम पीछे खींच लेते हैं, लेकिन प्रेमचंद ने इस संकट को अपनी शक्ति बना लिया। उन्होंने यह निश्चय किया कि अब वे हिंदी में लेखन करेंगे और अपने विचारों को एक नई भाषा के माध्यम से व्यक्त करेंगे।

यह निर्णय जितना साहसिक था, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी। हिंदी भाषा से लगभग अपरिचित व्यक्ति के लिए उसमें लेखन करना आसान नहीं था। जब उनके एक मित्र ने उनसे यह प्रश्न किया कि बिना हिंदी जाने वे इसमें कैसे लिखेंगे, तब उनका उत्तर उनके आत्मविश्वास का प्रतीक था। उन्होंने स्पष्ट कहा कि उर्दू और हिंदी में मूलभूत अंतर नहीं है, केवल लिपि का भेद है, और यदि मन में दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी कार्य कठिन नहीं होता। यह विचार केवल एक उत्तर नहीं था, बल्कि उनके जीवन का दर्शन था, जिसने उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी।

इसके बाद उन्होंने पूरी निष्ठा और लगन के साथ देवनागरी लिपि सीखनी शुरू की। उन्होंने यह नहीं सोचा कि यह प्रक्रिया कितनी कठिन होगी या इसमें कितना समय लगेगा, बल्कि उन्होंने अपने लक्ष्य को केंद्र में रखा और निरंतर अभ्यास करते रहे। यही सतत प्रयास और आत्मविश्वास उन्हें उस मुकाम तक ले गया, जहां वे हिंदी साहित्य के शिखर पुरुष बन गए। उनकी यह यात्रा यह दर्शाती है कि सफलता का मार्ग केवल प्रतिभा से नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयास से बनता है।

प्रेमचंद ने हिंदी साहित्य को जो योगदान दिया, वह अमूल्य है। उनका उपन्यास 'गोदान' आज भी भारतीय समाज की गहराइयों को समझने का एक सशक्त माध्यम माना जाता है। उनकी कहानियाँ केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि समाज का दर्पण हैं, जो उस समय की सामाजिक, आर्थिक और नैतिक परिस्थितियों को सजीव रूप में प्रस्तुत करती हैं। उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों की आवाज को मुखर किया और अन्याय के खिलाफ एक सशक्त स्वर उठाया।

उनकी सफलता यह भी सिखाती है कि किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए यह आवश्यक नहीं कि हमारे पास प्रारंभ से ही सभी योग्यताएँ हों। कई बार हमें अपनी यात्रा के दौरान ही सीखना पड़ता है और यही सीखने की प्रक्रिया हमें मजबूत बनाती है। यदि हम यह सोचकर रुक जाएं कि हमें अभी सब कुछ नहीं आता, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन यदि हम अपने भीतर यह विश्वास रखें कि हम सीख सकते हैं, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती।

आज के समय में, जब लोग छोटी-छोटी असफलताओं से घबरा जाते हैं और अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, तब प्रेमचंद का जीवन हमें धैर्य और दृढ़ता का पाठ पढ़ाता है। वह हमें यह सिखाता है कि असफलताएँ अंत नहीं होतीं, बल्कि वे एक नई शुरुआत का संकेत होती हैं। यदि हम उन्हें सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें, तो वे हमें और अधिक मजबूत और सक्षम बना सकती हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि प्रेमचंद ने अपने लेखन को केवल व्यक्तिगत अभिव्यक्ति तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे समाज के उत्थान का माध्यम बनाया। उन्होंने अपनी कलम के जरिए समाज की कुरीतियों, विषमताओं और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। यही कारण है कि उनका साहित्य आज भी उतना ही प्रासंगिक है, जितना उनके समय में था। यह हमें यह सिखाता है कि सच्ची सफलता वही है, जो समाज के लिए उपयोगी हो और लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाए।

अंततः, प्रेमचंद का जीवन यह स्पष्ट करता है कि अडिग निश्चय और आत्मविश्वास से कोई भी व्यक्ति अपनी सीमाओं को पार कर सकता है। चाहे भाषा की बाधा हो, संसाधनों की कमी हो या परिस्थितियों की कठिनाई—यदि हमारे भीतर संकल्प की शक्ति है, तो हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह केवल एक प्रेरणादायक कहानी नहीं, बल्कि एक जीवन-दर्शन है, जो हमें यह सिखाता है कि असंभव कुछ भी नहीं होता।

इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि जब व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाता है और उसे पाने के लिए निरंतर प्रयास करता है, तो सफलता उसके कदम चूमती है। प्रेमचंद की यह प्रेरक यात्रा हमें यह विश्वास दिलाती है कि दृढ़ निश्चय के साथ उठाया गया एक कदम भी इतिहास रच सकता है और साधारण जीवन को असाधारण बना सकता है।

सत्ता में समानता

भारत का लोकतंत्र केवल एक प्रशासनिक ढांचा नहीं, बल्कि समानता, न्याय और जनभागीदारी की सशक्त अभिव्यक्ति है। जब इस व्यवस्था में आधी आबादी—नारी शक्ति—को सार्थक और प्रभावी प्रतिनिधित्व मिलता है, तभी विकास संतुलित और समावेशी बनता है। "नारी शक्ति वंदन अधिनियम" इसी विचार का प्रतीक है, जो केवल संवैधानिक संशोधन नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना और ऐतिहासिक संघर्ष की परिणति है। भारतीय इतिहास इस सत्य का साक्षी है कि महिलाओं ने सदैव नेतृत्व और सुशासन में अपनी क्षमता सिद्ध की है। अहिल्याबाई होलकर इसका उत्कृष्ट उदाहरण हैं, जिन्हें 'प्रजा की माता' और आदर्श शासिका के रूप में स्मरण किया जाता है। उनके शासन में न्याय, संवेदनशीलता और लोक कल्याण सर्वोपरि रहे। स्वतंत्र भारत में 73वें संविधान संशोधन (1993) ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण सुनिश्चित कर लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर सशक्त बनाया। आज लगभग 13 लाख निर्वाचित महिला प्रतिनिधि इस परिवर्तन की सशक्त मिसाल हैं। कई राज्यों ने इसे बढ़ाकर 50% तक कर दिया है, जिससे स्थानीय शासन में महिलाओं की निर्णायक भूमिका स्थापित हुई है। भले ही "सरपंच पति" जैसी प्रवृत्तियाँ सामने आईं, परंतु इसके पीछे एक गहरी क्रांति थी—ग्रामीण भारत में पहली पीढ़ी की महिला नेताओं का उदय। धीरे-धीरे महिलाएँ निष्क्रिय मतदाता से सक्रिय राजनीतिक शक्ति में परिवर्तित हो गईं। उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में महिला प्रतिनिधियों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया है। सितंबर 2023 में भारतीय संसद ने इस ऐतिहासिक विधेयक को पारित कर लोकतांत्रिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ा। 106वें संविधान संशोधन के रूप में लाया गया यह अधिनियम लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित करता है, जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं को भी समुचित प्रतिनिधित्व दिया गया है। यह कदम केवल विधायी परिवर्तन नहीं, बल्कि लोकतंत्र को अधिक न्यायपूर्ण, समावेशी और प्रतिनिधिक बनाने का दूरदर्शी प्रयास है। वर्तमान भारत में एक दिलचस्प किंतु चिंताजनक विरोधाभास उभरकर सामने आता है। महिलाएँ मतदान में पुरुषों के बराबर, बल्कि कई बार उनसे अधिक सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं। 2024 के आम चुनावों में महिलाओं का मतदान प्रतिशत लगभग 65.8% रहा, जो पुरुषों से थोड़ा अधिक है। पिछले वर्षों में असम, तमिलनाडु और ओडिशा जैसे राज्यों में भी महिलाओं ने मतदान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया है, जो उनकी जागरूकता और लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके बावजूद, संसद में उनका प्रतिनिधित्व अब भी लगभग 14–15% तक सीमित है। उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया में पुरुष वर्चस्व आज भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यह अंतर केवल संख्याओं का नहीं, बल्कि संरचनात्मक असमानताओं का परिणाम है। चुनावी राजनीति में वित्तीय संसाधनों तक महिलाओं की सीमित पहुँच, सामाजिक जिम्मेदारियों का असंतुलित बोझ और व्यक्तिगत सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियाँ उनके राजनीतिक सफर को कठिन बनाती हैं। यह स्पष्ट करता है कि केवल इच्छा और क्षमता पर्याप्त नहीं—सशक्त भागीदारी के लिए उन्हें ठोस संस्थागत और संरचनात्मक समर्थन की आवश्यकता है।

इसी निरंतर जागरूकता, संघर्ष और सहभागिता का परिणाम है—"नारी शक्ति वंदन अधिनियम", जो भारत के लोकतांत्रिक विकास में एक नए युग का उद्घोष करता है। यह अधिनियम केवल एक नीति नहीं, बल्कि सशक्त भारत के संकल्प का सजीव प्रतीक है। यह महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने का माध्यम भर नहीं, बल्कि उस लोकतांत्रिक चेतना का विस्तार है जहाँ निर्णय प्रक्रिया में नारी की आवाज़ समान रूप से गूंजती है और उसे सम्मानपूर्वक स्थान मिलता है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने नारी सशक्तिकरण .. "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ", "उज्ज्वला योजना", "जन धन योजना", "प्रधानमंत्री आवास योजना" और "सुकन्या समृद्धि योजना" जैसी पहलों ने देश की करोड़ों महिलाओं के जीवन में आत्मविश्वास, सुरक्षा और स्वाभिमान का संचार किया है। 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को उज्ज्वला योजना का लाभ, 70% से अधिक घरों का स्वामित्व महिलाओं के नाम, और 3 करोड़ से अधिक सुकन्या समृद्धि खाते—ये आंकड़े नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की नई कहानी हैं, जहाँ नारी अब लाभार्थी नहीं, बल्कि परिवर्तन की वाहक बन चुकी है।.. इसी सशक्त यात्रा का अगला स्वाभाविक और निर्णायक कदम —"नारी शक्ति वंदन अधिनियम", जो नारी नेतृत्व को नई ऊँचाइयों तक ले जाने का सशक्त माध्यम है। इसकी रोटेशन व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं को नेतृत्व का अवसर मिले, जिससे लोकतंत्र अधिक व्यापक, समावेशी और गतिशील बने।

इस अधिनियम की सबसे बड़ी शक्ति इसके दूरगामी प्रभाव में निहित है। यह एक मजबूत "क्रिटिकल मास" तैयार करेगा, जो प्रतीकात्मक भागीदारी को वास्तविक शक्ति में बदल देगा। यह पंचायत से संसद तक एक सुदृढ़ नेतृत्व श्रृंखला का निर्माण करेगा और राजनीति की प्राथमिकताओं को नया स्वर देगा—जहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और सामाजिक सुरक्षा केंद्र में होंगे। साथ ही, यह अधिनियम राजनीति की संस्कृति को भी रूपांतरित करने की क्षमता रखता है—संवाद, संवेदनशीलता और समावेशन पर आधारित एक नई राजनीतिक धारा का निर्माण करते हुए यह केवल महिलाओं को स्थान नहीं देता, बल्कि लोकतंत्र को अधिक मानवीय, संतुलित और प्रभावी बनाता है। यदि यह प्रक्रिया सफलतापूर्वक आगे बढ़ती है, तो भारत एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायक उपलब्धि हासिल करेगा—जहाँ सामाजिक वास्तविकता और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के बीच सच्चा सामंजस्य स्थापित होगा। भारतीय महिलाओं ने मतदाता के रूप में अपनी जागरूकता, परिपक्वता और निर्णायक शक्ति पहले ही सिद्ध कर दी है; अब समय है कि राजनीतिक संरचना भी उसी शक्ति और परिपक्वता को प्रतिबिंबित करे।

अभियान

"अक्षय तृतीया से मोक्ष द्वार तक: चारधाम यात्रा 2026 की दिव्य पुकार"

जब हिमालय की गोद में बसे देवस्थान अपने कपाट खोलते हैं, तो वह केवल मंदिरों के द्वार खुलने की घटना नहीं होती, बल्कि वह मानव आत्मा के लिए मोक्ष के मार्ग का उद्घाटन होता है। वर्ष 2026 में यह दिव्य क्षण 19 अप्रैल को पवित्र पर्व अक्षय तृतीया के साथ आ रहा है, जब चारधाम यात्रा का शुभारंभ होगा। यह केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि श्रद्धा, तप, विश्वास और आत्मशुद्धि की एक अद्भुत साधना है, जिसमें हर कदम पर भक्ति की अनुभूति होती है और हर श्वास में ईश्वर का स्मरण।

चारधाम—यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम—ये चारों धाम न केवल भौगोलिक रूप से कठिन हैं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत ऊंचे माने जाते हैं। कहा जाता है कि इन चारों धामों के दर्शन से मनुष्य जन्मों के पापों से मुक्त होकर मोक्ष के मार्ग की ओर अग्रसर होता है।

स वर्ष यात्रा का प्रारंभ 19 अप्रैल को होगा, जब यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट एक साथ श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे। इसके बाद 22 अप्रैल को केदारनाथ और 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के द्वार भी भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे।

यह संयोग अत्यंत शुभ माना जा रहा है, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन किए गए पुण्य कार्य अक्षय फल देते हैं—अर्थात उनका फल कभी समाप्त नहीं होता।

यात्रा का पहला पड़ाव यमुनोत्री धाम है, जहां मां यमुना का वास माना जाता है। यहां की शांति, हिमालय की शीतल हवाएं और प्राकृतिक गर्म जलकुंड श्रद्धालुओं को अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। मान्यता है कि मां यमुना के दर्शन से आयु, आरोग्य और पापों से मुक्ति मिलती है। जब भक्त यहां पहुंचते हैं, तो उनके भीतर का अहंकार धीरे-धीरे पिघलने लगता है और आत्मा ईश्वर के समीप जाने लगती है।

इसके बाद गंगोत्री धाम आता है, जो मां गंगा का उद्गम स्थल माना जाता है। यहां की पवित्रता और दिव्यता इतनी प्रबल होती है कि हर व्यक्ति अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस करता है। कहा जाता है कि राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने मां गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर पृथ्वी पर प्रवाहित किया। गंगोत्री के दर्शन से मन, वचन और कर्म की शुद्धि होती है, और व्यक्ति जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने लगता है।

तीसरा और सबसे कठिन पड़ाव केदारनाथ धाम है, जो भगवान शिव का पवित्र ज्योतिर्लिंग है। समुद्र तल से लगभग 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर हिमालय की कठोरता और भक्ति की पराकाष्ठा का प्रतीक है। यहां पहुंचना जितना कठिन है, उतना ही दिव्य अनुभव भी है। कहा जाता है कि पांडवों ने अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए यहां भगवान शिव की आराधना की थी। केदारनाथ के दर्शन से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और आत्मा को शांति मिलती है।

अंतिम पड़ाव बद्रीनाथ धाम है, जहां भगवान विष्णु नर-नारायण रूप में विराजमान हैं। यह स्थान भक्ति और ज्ञान का संगम है। यहां की अखंड ज्योति और अलौकिक वातावरण भक्तों को एक अलग ही आध्यात्मिक स्तर पर ले जाता है। माना जाता है कि बद्रीनाथ के दर्शन से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन का अंतिम उद्देश्य पूर्ण हो जाता है।

चारधाम यात्रा केवल शरीर की यात्रा नहीं है, यह आत्मा की यात्रा है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां चाहे कितनी भी क्यों न हों, यदि संकल्प दृढ़ हो तो हर मंजिल प्राप्त की जा सकती है। हिमालय की कठिन राहें हमें धैर्य, संयम और श्रद्धा का पाठ पढ़ाती हैं। हर मोड़ पर प्रकृति हमें यह याद दिलाती है कि हम केवल एक यात्री हैं और हमारा वास्तविक घर ईश्वर के चरणों में है।

इस यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को कई सावधानियां भी बरतनी चाहिए। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ऑक्सीजन की कमी, ठंड और कठिन रास्तों के कारण शारीरिक रूप से तैयार रहना बेहद जरूरी है। यात्रा पर निकलने से पहले स्वास्थ्य जांच, आवश्यक दवाइयों का साथ रखना और मौसम के अनुसार कपड़े पहनना अनिवार्य है। लेकिन इन सभी तैयारियों के बीच सबसे महत्वपूर्ण है मन की शुद्धता और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास।

जब कोई भक्त चारधाम यात्रा पूरी करता है, तो वह केवल चार मंदिरों के दर्शन नहीं करता, बल्कि वह अपने भीतर छिपे ईश्वर को खोज लेता है। यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि सच्चा सुख बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही मौजूद है। जब हम अपने अहंकार, इच्छाओं और मोह को त्यागकर ईश्वर की शरण में जाते हैं, तभी हमें सच्ची शांति और आनंद की अनुभूति होती है।

अंततः, 2026 की चारधाम यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक क्रांति है—एक ऐसा अवसर, जहां हर व्यक्ति अपने जीवन को नया अर्थ दे सकता है। अक्षय तृतीया के इस पावन अवसर पर शुरू होने वाली यह यात्रा हर भक्त को यह संदेश देती है कि यदि संकल्प सच्चा हो और भक्ति में शक्ति हो, तो हर मार्ग आसान हो जाता है और हर लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। यही है चारधाम की महिमा, यही है भक्ति का सार और यही है जीवन का परम सत्य।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002 and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

सूरत में बिना लाइसेंस वाला आरओ पानी, नकली आइसक्रीम और जूस स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहे हैं

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। जीवन के लिए जल अत्यंत आवश्यक है। जल का अर्थ है जल, और यह हमारी आवश्यकता है। वर्तमान में, जब भीषण गर्मी पड़ रही है, तो स्वाभाविक है कि हर किसी को पानी की आवश्यकता है और इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पानी अब व्यापार का एक अभिन्न अंग बन गया है।

इस ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए, कुछ बोली लगाने वाले अब सफेद पानी के नाम पर काला धन कमा रहे हैं। इस जल व्यापार का मतलब आरओ प्लांट है, जिसके लिए कम से कम 300x500 वर्ग फुट जगह की आवश्यकता होती है। इसमें एक आरओ मशीन, भंडारण टैंक और खाली व भरी बोतलों और जगों को रखने की जगह होनी चाहिए। साथ ही, 500 लीटर प्रति घंटा (लीटर प्रति घंटा), 1000 लीटर प्रति घंटा, 2000 लीटर प्रति घंटा (एलपीएच) की बोतलें भरने वाली मशीन सक्षम प्राधिकारी को दिखानी होती है। इसके अलावा, एफएसएसएआई लाइसेंस, व्यापार लाइसेंस और स्वास्थ्य संबंधी सभी दस्तावेज सक्षम प्राधिकारी को दिखाने होते हैं। इस प्रकार, उपरोक्त सभी नीतियों और नियमों का पालन करते हुए आरओ प्लांट स्थापित करके काम शुरू किया जा सकता है।

लेकिन अब शहर में, कुछ बोली लगाने वाले जनता की मांग का फायदा उठाकर, बोरवेल के पानी या एसएमसी नल कनेक्शन के केवल 10x10 वर्ग फुट के कमरे का उपयोग करके और उसमें से एक लंबी रबर पाइप के माध्यम से 20 लीटर पानी की बोतलें (जार) भरकर टेम्पो के माध्यम से भेजकर काला धन कमा रहे हैं। इस पानी को ग्लाइकोल के साथ क्लोरीन की गोलियां मिलाकर ठंडा किया जाता है। इन पानी की बोतलों पर आईएसआई का कोई प्रमाण पत्र नहीं होता। यह पानी लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। आज यही पानी घरों, किराना दुकानों, डेयरी, होटलों, रेस्तरां, स्कूलों, कॉलेजों, कार्यालयों, कारखानों, जिम, अस्पतालों, फ्लैटों और आवासीय सोसाइटियों में पहुंचाया जा रहा है। 20 लीटर की बोतलों और जगों में पानी की गुणवत्ता और परीक्षण की जांच नहीं की जाती और न ही महीनों तक इन्हें साफ किया जाता है। जहां ऐसे पानी के पंप चल रहे हैं, वे ज्यादातर झुग्गी-झोपड़ी वाले इलाकों और औद्योगिक

क्षेत्रों में हैं। जहां कोई जांच नहीं होती, वहां लोगों को पसंद आने वाले ब्रांड की कंपनियों का पानी पिलाया जाता है। यह पानी अधिकतर 500 मिलीलीटर से लेकर एक लीटर, दो लीटर और पांच लीटर की बोतलों में पैक करके बेचा जाता है। इस तरह के पानी की गुणवत्ता की कोई गारंटी नहीं है क्योंकि स्वास्थ्य विभाग हमेशा से ही एक "भ्रष्ट विभाग" रहा है और इसके अधिकारी इस तरह की किसी भी जांच में रुचि नहीं रखते। इसी वजह से सफेद पानी का काला धंधा करने वालों की संख्या दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। और वे लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करके अपनी दौलत बढ़ा रहे हैं।

अब बात करते हैं आइसक्रीम की, जिसका सेवन गर्मियों में खूब होता है। इस आइसक्रीम में कस्टर्ड पाउडर, दूध और अलग-अलग फ्लेवर मिलाकर इसे मशहूर कंपनियों के असली ब्रांड्स की तरह आकर्षक और रंगीन बनाया जाता है। ग्राहकों को लुभाने के लिए इसकी खास पैकेजिंग तैयार की जाती है और यह आइसक्रीम बाजार में बिकती है। पहली नजर में ग्राहक को लगता है कि यह किसी मशहूर ब्रांड की आइसक्रीम है। लेकिन पैकेजिंग खोलने पर पता चलता है कि असली स्वाद तो नहीं, लेकिन यह नकली है, मानो मिट्टी में पैसा गँवाना हो। इस तरह की घटिया आइसक्रीम को आकर्षक पैकेजिंग में पैक करके कोल्ड ड्रिंक की दुकानों, पान पार्लरों, बेकरियों आदि को भेजा जाता है और धड़ल्ले से बिकती है। कोई जाँच-पड़ताल न होने के कारण लोग इसे खाकर अपनी सेहत को भी नुकसान पहुँचा रहे हैं।

इसी तरह, पोटेशियम परमैंगनेट (KMno 4) से पकाए गए और सड़े हुए आम के जूस के डिब्बे आकर्षक पैकेजिंग में जानी-मानी कंपनियों के नाम से बेचे जा रहे हैं। इनमें ज्यादातर सैकरीन का इस्तेमाल होता है। सड़क किनारे खड़ी छोटी-बड़ी ट्रकों के डिब्बों पर आम के जूस के नाम पर यही जूस लोगों को पिलाया जा रहा है। इसके साथ ही तरबूज के जूस में भी सैकरीन का इस्तेमाल किया जाता है। चूंकि मौजूदा गर्मी के कारण लोग जूस पीना ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए इस तरह की बिक्री खूब हो रही है। जिसकी कोई जांच नहीं करता या करता ही नहीं है। अब बात करते हैं ठंडी बर्फ की, यहां जिस पानी से बर्फ बनाई जाती है वह भी साफ नहीं होता। और जब इससे बनी बर्फ गन्ने के रस, आइस बॉल, जूस, नींबू पानी, सोडा या कोल्ड ड्रिंक्स के जरिए लोगों तक पहुंचाई जा रही है, और लोग शायद "गर्मी में भी ठंडक का एहसास" का पूरा फायदा उठा रहे हैं, तो क्या यह आश्चर्य की बात है कि जिम्मेदार सरकारी तंत्र भी "क्या करें?" की नीति अपना रहा है?

सांसदों और विधायकों की बढ़ती संख्या और सुविधाओं के कारण जनता पर वित्तीय बोझ बढ़ने का डर

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। देश में लोग जनता के पैसे से जूझ रहे हैं और उनकी सात पीढ़ियां जैसे-तैसे कमा रही हैं। जब यह राजनीतिक समूह जनता के पैसे पर जी रहा है, तो इनकी संख्या में आधे की भी वृद्धि जनता की कमर तोड़ देगी। क्या इसमें कोई संदेह है? क्योंकि हम न केवल अपने सांसदों, विधायकों या मंत्रियों के वेतन, किराए या बंगलों का बोझ उठा रहे हैं, बल्कि उनके कर्मचारियों, उनके वेतन और उनके लिए नए कार्यालयों, आवासों, नए कर्मचारियों का भी बोझ उठा रहे हैं। न केवल सुरक्षा व्यवस्था, बल्कि इन सेवकों की पेंशन भी हमारी जेब से ही निकलेगी।

ज़रा देखिए कि हम जैसे गरीब लोगों का पेट फाड़कर इकट्ठा किया गया कर इन चुने हुए सांसदों और विधायकों पर कैसे खर्च होता है। अगर हम आज के चुने हुए सांसदों का ही उदाहरण लें, तो उनमें से 46 प्रतिशत पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। यानी ये सांसद भी बेदाग नहीं हैं। इसके अलावा, इन सांसदों में से 93 प्रतिशत, यानी अधिकांश सांसद करोड़पति हैं, जिन्हें आम तौर पर हमारे पैसे की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वे बड़े चाव से सारे लाभ उठाते हैं। विधायकों का भी यही हाल है। इसके अलावा, भले ही वे हर महीने लाखों रुपये खर्च करते हों, फिर भी उन्हें

अपने परिवार के साथ दिल्ली में एक बंगले में मुफ्त रहने को मिलता है, और इस परिवार के साथ उन्हें ट्रेन, हवाई जहाज में मुफ्त यात्रा, मुफ्त चिकित्सा सुविधा, समर्पित कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, वाहन आदि की सुविधा मिलती है। अगर हम उनके खर्चों को जोड़ें, तो दिमाग चकरा जाएगा। यह भी कहना कि ऊपर बताए गए सांसद-विधायी विभाग के फंड निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए दिए जाते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि इस भ्रष्ट और भ्रष्ट युग में विकास कौन करता है। इसके अलावा, यह मामला भाजपा, कांग्रेस या वामपंथी-दक्षिणपंथी दलों का नहीं है, बल्कि यह सभी भारतीयों और करों के बोझ तले दबे सभी राजनीतिक दलों का मुद्दा है। ये राजनीतिक दल मेरी और आपकी मेहनत की कमाई पर लगाए गए भारी करों से जमा किए गए धन का बेधड़क इस्तेमाल कर रहे हैं। और वह भी हमसे बिना पूछे। वैसे, जनमत की बात करने वाले शासकों या नेताओं को इतने बड़े और महत्वपूर्ण मामले पर जनता की राय लेना क्यों जरूरी नहीं लगा? जनमत की बात तो छोड़िए, वे हमें इतना तुच्छ समझते हैं कि इस मामले में हमें विश्वास में लेना भी उचित नहीं समझा?

सूरत में छात्रों का फूटा गुस्सा: GCAS पोर्टल की गड़बड़ियों पर वीएनएसजीयू गेट पर उग्र प्रदर्शन, एडमिशन प्रक्रिया ठप होने से बढ़ी बेचैनी

सूरत। उच्च शिक्षा में डिजिटल व्यवस्था को आसान और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से बनाए गए पोर्टल जब खुद परेशानी का कारण बन जाएं, तो असंतोष का फूटना तय हो जाता है। ऐसा ही दृश्य उस समय देखने को मिला जब वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर बड़ी संख्या में छात्र इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। GCAS पोर्टल में लगातार आ रही तकनीकी खामियों ने छात्रों की चिंता को गुस्से में बदल दिया, और यह गुस्सा सड़कों पर नारेबाजी और प्रदर्शन के रूप में सामने आया।

इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया, जिसके बैनर तले सैकड़ों छात्र विश्वविद्यालय परिसर के बाहर जमा हुए। छात्रों के हाथों

में तख्तियां थीं, नारों में नाराजगी साफ झलक रही थी, और माहौल पूरी तरह से आक्रोश से भरा हुआ था। छात्रों का कहना था कि GCAS पोर्टल में लगातार आ रही तकनीकी दिक्कतों ने उनके भविष्य को अनिश्चितता में डाल दिया है।

छात्रों के मुताबिक, एडमिशन प्रक्रिया के सबसे महत्वपूर्ण चरण—ऑनलाइन फॉर्म भरना, दस्तावेज अपलोड करना और वेरिफिकेशन—तीनों में गंभीर बाधाएं आ रही हैं। कई छात्रों ने बताया कि वे घंटों तक पोर्टल पर प्रयास करते रहते हैं, लेकिन या तो साइट क्रैश हो जाती है या डेटा सेव नहीं होता। कुछ मामलों में आवेदन अधूरा रह जाता है, तो कहीं अपलोड किए गए दस्तावेज गायब हो जाते हैं। इस तकनीकी अव्यवस्था के चलते कई योग्य छात्र समय सीमा के भीतर आवेदन जमा नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उनका एक पूरा शैक्षणिक वर्ष दांव पर लगने का खतरा पैदा हो गया है।

स्थिति तब और गंभीर हो गई जब छात्रों ने यह आरोप लगाया कि इस समस्या को लेकर वे कई बार विश्वविद्यालय प्रशासन से संपर्क कर चुके हैं, लेकिन हर बार उन्हें केवल आश्वासन ही मिला। कोई ठोस समाधान या वैकल्पिक व्यवस्था अब तक लागू नहीं की गई, जिससे छात्रों में निराशा और आक्रोश लगातार बढ़ता गया। इसी निराशा ने अंततः उन्हें विरोध प्रदर्शन के लिए मजबूर कर दिया।

प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने केवल नारेबाजी ही नहीं की, बल्कि प्रतीकात्मक रूप से GCAS पोर्टल का पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज कराया। इसके साथ ही मटके फोड़कर उन्होंने यह संदेश देने की कोशिश की कि उनकी उम्मीदें और धैर्य अब टूट चुका है। यह दृश्य विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए एक स्पष्ट चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है कि समस्या को अब नजरअंदाज करना संभव नहीं है।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं किया गया, तो आंदोलन को और व्यापक और उग्र रूप दिया जाएगा। उन्होंने मांग की कि या तो GCAS पोर्टल को तत्काल प्रभाव से दुरुस्त किया जाए, या फिर ऑफलाइन या किसी वैकल्पिक माध्यम से एडमिशन प्रक्रिया शुरू की जाए, ताकि छात्रों का नुकसान न हो।

प्रदर्शन के बाद भले ही छात्र अपने-अपने घर लौट गए हों, लेकिन उनके मन में असंतोष अभी भी गहराई से बना हुआ है।

भारतीय स्वाद की वैश्विक उड़ान: महुआ और फेनी ने ब्रिटेन में दी दस्तक, विरासत पेयों की नई पहचान

लंदन। भारतीय परंपरा, कारीगरी और स्थानीय स्वाद अब सीमाओं को पार करते हुए वैश्विक बाजार में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। सदियों पुरानी जनजातीय संस्कृति से जुड़ा महुआ और गोवा की प्रसिद्ध फेनी अब ब्रिटेन के बाजार में 'इंडियन हेरिटेज ड्रिंक्स' के रूप में प्रवेश कर चुके हैं। यह केवल एक व्यापारिक पहल नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत को अंतरराष्ट्रीय मंच पर स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

ब्रिटेन में इन पारंपरिक पेयों को पेश करने का काम महाराजा ड्रिंक्स ने किया है, जिसने भारतीय पेयों की एक विशेष श्रृंखला लॉन्च की है। इस श्रृंखला में फेनी के तीन अलग-अलग प्रकार और एक महुआ पेय को शामिल किया गया है। कंपनी का उद्देश्य केवल उत्पाद बेचना नहीं, बल्कि उन कहानियों और परंपराओं को भी सामने लाना है, जिनसे ये पेय जुड़े हुए हैं।

महुआ, जो भारत के आदिवासी इलाकों में सदियों से तैयार किया जाता रहा है, केवल एक पेय नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक प्रतीक है। महुआ के फूलों से

बनने वाला यह पेय विशेष रूप से मध्य भारत और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में सामाजिक और धार्मिक आयोजनों का अभिन्न हिस्सा रहा है। अब यही महुआ अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी पहचान बनाने की ओर बढ़ रहा है। इसी तरह फेनी, जो गोवा की मिट्टी से जुड़ी एक पारंपरिक शराब है, अपने अनोखे स्वाद और निर्माण प्रक्रिया के लिए जानी जाती है। काजू और नारियल से बनने वाली फेनी की सुगंध और स्वाद इसे अन्य पेयों से अलग बनाते हैं।

इस नई श्रृंखला में फेनी के तहत काजू फेनी, नारियल फेनी और 'ओरो डे गोवा' नामक मसालेदार संस्करण शामिल किया गया है, जिसे गोवा की पारंपरिक आसवनशालाओं में तैयार किया गया है। वहीं महुआ पेय आंध्र प्रदेश के कारीगरों द्वारा तैयार किया गया है, जो पारंपरिक तकनीकों और स्थानीय संसाधनों का उपयोग करते हैं। यह विविधता इस बात को दर्शाती है कि भारत में पेयों की संस्कृति कितनी समृद्ध और बहुआयामी है।

कंपनी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी एनेबल जैमिसन ने इस पहल को एक सही समय पर उठाया गया कदम बताया है। उनका कहना है कि आज के उपभोक्ता केवल स्वाद ही नहीं, बल्कि उत्पाद की कहानी, उसकी उत्पत्ति और उसकी प्रामाणिकता को भी महत्व देते हैं। दुनिया भर में 'क्राफ्ट' और 'आर्टिजन' पेयों की मांग तेजी से बढ़ रही है, और ऐसे में भारतीय विरासत पेय एक नया आकर्षण बनकर उभर सकते हैं।

महाराजा ड्रिंक्स ने यह भी स्पष्ट किया है कि उनके उत्पाद केवल स्वाद तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे पर्यावरण और स्थिरता के प्रति भी प्रतिबद्ध हैं। जैविक प्रमाणन, टिकाऊ उत्पादन पद्धतियां, और पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग व परिवहन पर विशेष ध्यान दिया गया है। इससे यह पहल केवल व्यापारिक नहीं, बल्कि जिम्मेदार और सतत विकास की दिशा में भी एक कदम बन जाती है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह शुरुआत भारतीय पेयों के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक बड़ा अवसर खोल सकती है। जिस तरह भारतीय भोजन ने दुनिया भर में अपनी जगह बनाई है, उसी तरह अब पारंपरिक पेय भी वैश्विक स्तर पर पहचान बना सकते हैं। हालांकि, इसके साथ चुनौती भी जुड़ी है—स्थानीय स्वाद को अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ताओं के अनुरूप प्रस्तुत करना और उसकी गुणवत्ता को बनाए रखना। फिलहाल, ब्रिटेन में महुआ और फेनी की एंट्री ने यह संकेत दे दिया है कि भारतीय परंपरा अब केवल देश की सीमाओं तक सीमित नहीं है। यह दुनिया के सामने अपने असली रूप में आने के लिए तैयार है, और आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि ये विरासत पेय वैश्विक बाजार में कितनी गहराई तक अपनी जगह बना पाते हैं।

इश्क, शक और खौफनाक अंजाम: दुर्ग में प्रेम संबंध बना मौत की वजह, बी.एड छात्रा की गला घोंटकर हत्या

दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से सामने आई एक दर्दनाक घटना ने रिश्तों की जटिलता और उनमें पनपते अविश्वास के खतरनाक रूप को उजागर कर दिया है। यहां प्रेम संबंध में पनपे शक ने एक युवा छात्रा की जान ले ली, और एक ऐसा अपराध सामने आया जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र में बी.एड की पढ़ाई कर रही 26 वर्षीय छात्रा की उसके ही प्रेमी ने गला घोंटकर हत्या कर दी। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने खुद पुलिस को फोन कर इस घटना की जानकारी दी, जिसके बाद उसे तत्काल हिरासत में ले लिया गया।

मृतका की पहचान युनेश्वरी वर्मा के रूप में हुई है, जो खैरागढ़ जिले के चिचोला की रहने वाली थी और उच्च शिक्षा के लिए दुर्ग में रह रही थी। आरोपी कार्तिक राम साहू, जो बालोद का निवासी है, उसी कॉलेज में पढ़ाई के दौरान युनेश्वरी के संपर्क में आया था। दोनों की दोस्ती धीरे-धीरे गहरे प्रेम संबंध में बदल गई, लेकिन इसी रिश्ते में पनपता शक अंततः एक भयावह अपराध में बदल गया।

पुलिस के अनुसार, कार्तिक को लंबे समय से यह संदेह था कि युनेश्वरी का किसी अन्य

युवक के साथ भी संबंध है। यह शक धीरे-धीरे उसके मन में घर करता गया और दोनों के बीच अक्सर इसी बात को लेकर झगड़े होते रहते थे। कई बार यह विवाद इतना बढ़ जाता था कि दोनों के बीच बातचीत तक बंद हो जाती थी, लेकिन फिर किसी तरह मामला शांत हो जाता था। हालांकि, भीतर ही भीतर यह अविश्वास लगातार गहराता जा रहा था।

घटना वाले दिन भी यही विवाद एक बार फिर उभरा और इस बार स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। शुक्रवार दोपहर करीब एक बजे कार्तिक, युनेश्वरी को अपने किराए के कमरे पर लेकर गया। वहां दोनों के बीच इस मुद्दे को लेकर तीखी बहस शुरू हुई, जो धीरे-धीरे उग्र झगड़े में बदल गई। गुस्से और शक के अंधेपन में कार्तिक ने अपना आपा खो दिया और उसने युनेश्वरी का गला दबा दिया। यह हमला इतना अचानक और गंभीर था कि मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

हत्या के बाद घटनास्थल पर सन्नाटा छा गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। वारदात के तुरंत बाद आरोपी ने खुद पुलिस को फोन कर हत्या की जानकारी दी। यह कदम जितना चौंकाने वाला था, उतना ही इस बात का संकेत भी था कि घटना के बाद उसे अपने किए का एहसास हुआ या वह मानसिक दबाव में आ गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, आरोपी को हिरासत में लिया और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह मामला पूरी तरह से आपसी अविश्वास और शक से जुड़ा हुआ है, जो धीरे-धीरे एक खतरनाक रूप लेता गया। जांच में यह भी सामने आया है कि दोनों के बीच पहले भी कई बार इसी मुद्दे को लेकर विवाद हो चुका था, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि यह विवाद एक दिन इतनी भयावह घटना में बदल जाएगा।

यह घटना केवल एक आपराधिक मामला नहीं, बल्कि समाज के सामने एक गंभीर सवाल भी खड़ा करती है—क्या रिश्तों में बढ़ता अविश्वास और असुरक्षा की भावना लोगों को इस हद तक धकेल सकती है? विशेषज्ञ मानते हैं कि जब संवाद की जगह संदेह ले लेता है और भावनाओं पर नियंत्रण खत्म हो जाता है, तो ऐसे हादसे होने की आशंका बढ़ जाती है।

फिलहाल पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर यह दिखा दिया है कि प्यार, जो जीवन को संवार सकता है, वही जब शक और गुस्से में बदलता है तो विनाश का कारण भी बन सकता है।

महिला आरक्षण पर सियासी संग्राम तेज: केशव मौर्य का सपा-कांग्रेस पर तीखा हमला, बोले-'नारी शक्ति के विरोधियों को जनता देगी जवाब'

लखनऊ। महिला आरक्षण के मुद्दे पर देश की राजनीति में चल रही तीखी खींचतान अब और तेज होती नजर आ रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्षी दलों पर सीधा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के पक्ष में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े संवैधानिक संशोधन के विरोध में वोट कर इन दलों ने अपनी मंशा साफ कर दी है कि वे महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं देना चाहते।

केशव प्रसाद मौर्य ने अपने बयान में इन दलों की सोच को 'पुरुषवादी मानसिकता' से ग्रसित बताया और कहा कि ऐसे दल नहीं चाहते कि देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़े। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इसे हर हाल में लागू करके रहेगी। उनके अनुसार, यह केवल एक राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि देश की आधी आबादी को उनका अधिकार दिलाने का प्रश्न है।

इस पूरे विवाद को और तीखा बनाते हुए मौर्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा कि सपा और कांग्रेस को यह समझ लेना चाहिए कि नारी शक्ति का आक्रोश आने वाले चुनावों में उन्हें भारी पड़ेगा। उन्होंने राजनीतिक भविष्यवाणी करते हुए कहा कि वर्ष 2029 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस आधी रह जाएगी, जबकि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा का सफाया हो जाएगा। उन्होंने विपक्षी दलों के चुनावी सपनों पर तंज कसते हुए कहा कि ये केवल 'हसीन सपने' हैं, जो कभी पूरे नहीं होंगे।

इस मुद्दे पर ब्रजेश पाठक ने भी विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा में "नारी शक्ति वंदन अधिनियम" को पारित नहीं होने देने के लिए कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जिम्मेदार हैं। उनके अनुसार, यह केवल एक विधेयक को रोकना नहीं, बल्कि देश की लगभग 70 करोड़ महिलाओं के साथ विश्वासघात है। उन्होंने इसे बेहद निंदनीय बताते हुए कहा कि महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का अवसर छीन लेना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है।

ब्रजेश पाठक ने यह भी कहा कि विपक्ष को इस फैसले की कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि महिलाओं का आक्रोश केवल एक चुनाव तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हर स्तर पर, हर चुनाव में विपक्ष को इसका सामना करना पड़ेगा। उन्होंने भरोसा जताया कि महिलाओं को सम्मान और अधिकार दिलाने का अभियान लगातार जारी रहेगा और सरकार इस दिशा में पीछे नहीं हटेगी। इस पूरे घटनाक्रम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि महिला आरक्षण का मुद्दा अब केवल संसद की बहस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह देश की राजनीति का केंद्रीय विषय बन चुका है। एक ओर सत्ता पक्ष इसे महिलाओं के अधिकार और सशक्तिकरण से जोड़कर प्रस्तुत कर रहा है, वहीं विपक्ष की भूमिका पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में यह मुद्दा आने वाले चुनावों में निर्णायक भूमिका निभा सकता है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि महिला मतदाता अब भारतीय राजनीति में एक सशक्त और निर्णायक शक्ति बन चुकी हैं। ऐसे में महिला आरक्षण जैसे मुद्दे पर लिया गया हर राजनीतिक रुख सीधे चुनावी परिणामों को प्रभावित कर सकता है। फिलहाल, आरोप-प्रत्यारोप के इस दौर में यह देखना अहम होगा कि यह सियासी लड़ाई किस दिशा में जाती है और देश की महिलाएं इसे किस नजरिए से देखती हैं।

'फेल नहीं, फिर से मौका': मध्यप्रदेश में 10वीं-12वीं के छात्रों के लिए सेकंड चांस एग्जाम, 7 मई से नई शुरुआत

भोपाल। परीक्षा में एक बार चूक जाने का मतलब अब भविष्य खत्म होना नहीं रहेगा। मध्यप्रदेश सरकार ने 10वीं और 12वीं के छात्रों को बड़ी राहत देते हुए 'द्वितीय अवसर परीक्षा' यानी सेकंड चांस एग्जाम की घोषणा की है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में लिया गया यह फैसला लाखों छात्रों के लिए नई उम्मीद लेकर आया है, जो किसी कारणवश मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए, असफल रहे या अपने अंकों में सुधार करना चाहते हैं।

राज्य के माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश द्वारा आयोजित यह परीक्षा 7 मई से शुरू होकर 25 मई 2026 तक चलेगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 22 अप्रैल रात 12 बजे तक खुली रहेगी, जहां छात्र एमपी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से संचालित की जा रही है, जिससे छात्रों को सुविधा के साथ समय पर पंजीकरण का अवसर मिल सके।

इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसमें तीन श्रेणियों के विद्यार्थियों को शामिल होने का मौका दिया गया है—वे छात्र जो पहली परीक्षा में अनुपस्थित रहे, वे जो एक या अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, और वे भी जो अपने प्राप्त अंकों में सुधार करना चाहते हैं। यानी यह केवल 'फेल' छात्रों के लिए नहीं, बल्कि बेहतर प्रदर्शन की इच्छा रखने वालों के लिए भी एक सुनहरा अवसर है।

सरकार ने एक और महत्वपूर्ण प्रावधान करते हुए यह स्पष्ट किया है कि प्रथम और द्वितीय परीक्षा में से जो भी परिणाम बेहतर होगा, वही अंतिम रूप से मान्य किया जाएगा। इससे छात्रों पर यह दबाव नहीं रहेगा कि यदि वे दोबारा परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन न कर पाए, तो उनका पिछला परिणाम भी प्रभावित होगा। यह व्यवस्था छात्रों को बिना डर के बेहतर प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है।

प्रायोगिक विषयों को लेकर भी स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं। केवल वही छात्र प्रैक्टिकल परीक्षा में शामिल हो सकेंगे, जो उस हिस्से में अनुत्तीर्ण रहे हैं। इसके अलावा इस परीक्षा में विषय बदलने की अनुमति नहीं दी गई है, ताकि परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और स्थिरता बनी रहे।

यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भावना के अनुरूप मानी जा रही है, जिसमें छात्रों को लचीलेपन और अधिक अवसर देने पर जोर दिया गया है। शिक्षा व्यवस्था को अधिक मानवीय और छात्र-केंद्रित बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। खास बात यह भी है कि इस वर्ष किसी भी छात्र का परिणाम 'पूरक' घोषित नहीं किया गया, जिससे छात्रों के मानसिक दबाव को काफी हद तक कम करने का प्रयास किया गया है। जनसंपर्क अधिकारी संदीप कपूर ने इस पहल के पीछे की सोच को स्पष्ट करते हुए कहा कि यह निर्णय छात्रों को निराशा से बाहर निकालने और उन्हें एक और मौका देने के उद्देश्य से लिया गया है।

महिला आरक्षण पर सियासी संग्राम: पीएम मोदी का विपक्ष पर तीखा हमला, बोले-'नारी शक्ति के साथ हुआ अन्याय देश नहीं भूलेगा'

नई दिल्ली। देश की राजनीति में महिला आरक्षण को लेकर छिड़ा विवाद अब खुलकर सियासी टकराव में बदल गया है। शनिवार रात राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां एक ओर देश की माताओं और बहनों से माफी मांगते हुए अपनी भावनाएं व्यक्त कीं, वहीं दूसरी ओर विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें 'नारी शक्ति के अधिकारों का विरोधी' करार दिया। करीब 30 मिनट के इस संबोधन में प्रधानमंत्री का लहजा भावनात्मक भी रहा और आक्रामक भी, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि राजनीतिक स्वार्थ के चलते एक ऐतिहासिक अवसर खो दिया गया।

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत ही इस स्वीकारोक्ति से की कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन नहीं हो पाने से उन्हें गहरा दुख है। उन्होंने कहा कि यह केवल एक विधेयक नहीं, बल्कि देश की महिलाओं के सशक्तिकरण का प्रतीक था, जिसे संसद में व्यापक समर्थन मिलना चाहिए था। उन्होंने देश की महिलाओं से क्षमा मांगते हुए कहा कि सरकार की मंशा पूरी तरह स्पष्ट थी, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों ने इसे विफल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यह बयान सीधे तौर पर संसद में हाल ही में हुए घटनाक्रम की ओर इशारा था, जहां इस मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई।

अपने संबोधन में नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के चार प्रमुख दलों—भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी—को सीधे निशाने पर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि इन दलों की 'परिवारवादी' और 'स्वार्थी राजनीति' के कारण देश की महिलाओं को उनका अधिकार नहीं मिल सका। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद में जब महिला हित से जुड़ा प्रस्ताव गिरा, तब इन दलों के सदस्यों का व्यवहार निराशाजनक था और यह पूरे देश ने देखा।

प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में भावनात्मक अपील करते हुए कहा कि नारी सब कुछ भूल सकती है, लेकिन अपने सम्मान पर हुई चोट को कभी नहीं भूलती। उन्होंने विपक्षी दलों के व्यवहार को नारी सम्मान के खिलाफ बताते हुए कहा कि यह घटना देश की महिलाओं के मन में लंबे समय तक कसक बनकर रहेगी। उन्होंने इस मुद्दे को केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक और नैतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बताया।

अपने संबोधन को और धार देते हुए प्रधानमंत्री ने इस पूरे घटनाक्रम की तुलना 'भ्रूण हत्या' से की और कहा कि जिस तरह एक जीवन को जन्म लेने से पहले ही समाप्त कर दिया जाता है, उसी तरह महिला सशक्तिकरण के इस प्रयास को भी संसद में समाप्त कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके सहयोगी दल इस 'भ्रूण हत्या' के गुनहगार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह केवल महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ नहीं, बल्कि संविधान की भावना के भी खिलाफ है।

प्रधानमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि विपक्ष ने इस मुद्दे पर देश को गुमराह करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि कभी संख्या के आधार पर, तो कभी अन्य तकनीकी कारणों का हवाला देकर इस प्रस्ताव को रोकने का प्रयास किया गया। उनके अनुसार, यह सब एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को टालना था। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस का इतिहास महिलाओं को अधिकार देने के मामले में हमेशा संदिग्ध रहा है और इस बार भी उसने वही रवैया अपनाया। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने दो महत्वपूर्ण चुनावी राज्यों का भी जिक्र किया—तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल—जहां आने वाले दिनों में मतदान होना है। उन्होंने संकेत दिया कि इन राज्यों की जनता, विशेष रूप से महिलाएं, इस पूरे घटनाक्रम को ध्यान में रखकर अपना फैसला लेंगी। उन्होंने कहा कि यह चुनाव केवल सरकार बनाने का नहीं, बल्कि नारी सम्मान और अधिकारों की रक्षा का भी है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर एक और गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह न केवल खुद कमजोर हो चुकी है, बल्कि क्षेत्रीय दलों को भी मजबूत नहीं होने देना चाहती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 'परजीवी' की तरह अन्य दलों के सहारे अपनी राजनीतिक मौजूदगी बनाए रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन वह यह भी नहीं चाहती कि वे दल स्वतंत्र रूप से मजबूत बनें। यह टिप्पणी सीधे तौर पर विपक्षी गठबंधन की आंतरिक राजनीति पर सवाल खड़े करती है। इस पूरे संबोधन ने यह साफ कर दिया है कि महिला आरक्षण का मुद्दा अब केवल नीति का विषय नहीं रह गया है, बल्कि यह आने वाले चुनावों का एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। जहां एक ओर प्रधानमंत्री इसे नारी सम्मान और अधिकारों से जोड़कर प्रस्तुत कर रहे हैं, वहीं विपक्ष इस पर अपनी अलग व्याख्या दे रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह सियासी टकराव किस दिशा में जाता है और देश की जनता, खासकर महिलाएं, इसे किस नजरिए से देखती हैं।

पश्चिम रेलवे चलाएगी अहमदाबाद-मुंबई सेंट्रल एसी सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की भीड़ एवं मांग को ध्यान में रखते हुए अहमदाबाद-मुंबई सेंट्रल-अहमदाबाद एसी सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है।

ट्रेन संख्या 09088/09087 अहमदाबाद-मुंबई सेंट्रल-अहमदाबाद एसी सुपरफास्ट स्पेशल

ट्रेन संख्या 09088 अहमदाबाद-मुंबई सेंट्रल एसी सुपरफास्ट स्पेशल (06 ट्रिप) दिनांक 23 अप्रैल से 28 मई 2026 तक प्रति गुरुवार को अहमदाबाद से 22:40 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन शुक्रवार को 07:10 बजे मुंबई सेंट्रल पहुंचेगी।

इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09487 मुंबई सेंट्रल-अहमदाबाद एसी सुपरफास्ट स्पेशल (06 ट्रिप) दिनांक 22 अप्रैल से 27 मई 2026 तक प्रति बुधवार को मुंबई सेंट्रल से 23:20 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन गुरुवार को 07:20 बजे अहमदाबाद पहुंचेगी।

यह ट्रेन मार्ग में दोनों दिशाओं में गेरतपुर, वडोदरा, सूरत, वापी और बोरीवली स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में एसी 1-टियर, एसी 2-टियर एवं एसी 3-टियर श्रेणी के कोच रहेंगे।

ट्रेन संख्या 09088/09087 अहमदाबाद-मुंबई सेंट्रल-अहमदाबाद एसी सुपरफास्ट स्पेशल के लिए बुकिंग दिनांक 19 अप्रैल 2026 से सभी PRS काउंटर्स एवं IRCTC वेबसाईट पर उपलब्ध होगी।

ट्रेनों के समय, ठहराव एवं अन्य जानकारी के लिए www.enquiry.indianrail.gov.in का अवलोकन करें।

यात्रियों की सुविधा हेतु बसों की विशेष व्यवस्था

भारतीय रेलवे द्वारा यात्री सुविधाओं के उन्नयन एवं रेलवे अवसंरचना को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से बुलेट ट्रेन परियोजना के अंतर्गत गेरतपुर–अहमदाबाद खंड पर प्रीकास्टेड पोर्टल बीम की स्थापना का कार्य किया जाएगा। इस कार्य के लिए दिनांक 19 अप्रैल, 2026 को ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाएगा।

इस ट्रैफिक ब्लॉक के कारण कुछ ट्रेनों के संचालन में अस्थायी परिवर्तन किया गया है। इसी क्रम में ट्रेन संख्या 20901 मुंबई सेंट्रल–गांधीनगर केपिटल वंदे भारत एक्सप्रेस को वटवा स्टेशन पर समाप्त (शॉर्ट टर्मिनेट) किया जाएगा।

यात्रियों को निर्बाध एवं सुगम यात्रा सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से अहमदाबाद मंडल **द्वारा दिनांक 19 अप्रैल को विशेष बसों की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है—**

- ▶▶वटवा से अहमदाबाद के लिए 16 एसी बसों की व्यवस्था की गई है।
- ▶▶वटवा से गांधीनगर के लिए 2 एसी बसों की व्यवस्था की गई है।

यह विशेष व्यवस्था यात्रियों को सुरक्षित एवं आरामदायक परिवहन उपलब्ध कराने के लिए की गई है, जिससे यात्रा में किसी प्रकार की असुविधा न हो।

आसमान से बदलेगा युद्ध का चेहरा: अब हेलीकॉप्टर और विमानों से तैनात होंगे ड्रोन, भारतीय वायुसेना की नई रणनीति

नई दिल्ली। बदलते वैश्विक युद्ध परिदृश्य ने आधुनिक सैन्य रणनीतियों की दिशा ही बदल दी है और अब आसमान में लड़ाई सिर्फ फाइटर जेट्स तक सीमित नहीं रह गई है। भारतीय वायु सेना ने इस नई वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत अब हेलीकॉप्टर और मालवाहक विमानों से सीधे ड्रोन और लोइटरिंग म्यूनिशंस तैनात किए जाएंगे। यह पहल न केवल तकनीकी उन्नति का संकेत है, बल्कि भविष्य के युद्धों के स्वरूप को समझते हुए की गई रणनीतिक तैयारी भी है। मिडिल ईस्ट में हाल के संघर्षों ने दुनिया भर की सेनाओं को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि पारंपरिक युद्ध के तरीके अब तेजी से अप्रासंगिक होते जा रहे हैं। छोटे, सटीक और कम लागत वाले ड्रोन ने महंगे हथियारों और भारी सैन्य प्लेटफॉर्म्स को चुनौती देना शुरू कर दिया है। ऐसे में भारतीय वायु सेना का यह कदम समय के साथ तालमेल बिठाने का प्रयास माना जा रहा है। वायुसेना ने हाल ही में हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जा सकने वाले ड्रोन के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (RFP) जारी किया है, जबकि मालवाहक विमानों से तैनात होने वाले लोइटरिंग म्यूनिशंस के लिए रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन (RFI) आमंत्रित किया गया है।

लोइटरिंग म्यूनिशंस, जिन्हें आम भाषा में 'कामीकाज़े ड्रोन' भी कहा जाता है, युद्धक्षेत्र में एक नई क्रांति लेकर आए हैं। ये ड्रोन लक्ष्य के ऊपर लंबे समय तक मंडराते रहते हैं और सही मौके पर खुद को विस्फोट के साथ लक्ष्य पर गिरा देते हैं। इस तकनीक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह रियल-टाइम इंटेलिजेंस और सटीक हमले की क्षमता को एक साथ जोड़ती है। अब जब इन्हें हेलीकॉप्टर या ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया जाएगा, तो इनकी पहुंच और प्रभाव दोनों कई गुना बढ़ जाएंगे। इस नई रणनीति से भारतीय वायुसेना को कई महत्वपूर्ण फायदे मिलने की उम्मीद है। सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि लड़ाकू विमानों पर निर्भरता कम हो जाएगी। अभी तक कई मिशनों के लिए फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करना पड़ता था, जो महंगा और जोखिम भरा होता है। लेकिन अब ड्रोन के जरिए उन्हीं लक्ष्यों को कम लागत और कम जोखिम में साधा जा सकेगा। इससे न केवल संसाधनों की बचत होगी, बल्कि पायलट्स की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।

इसके अलावा, हेलीकॉप्टर से ड्रोन लॉन्च करने की क्षमता युद्ध के मैदान में लचीलापन बढ़ाएगी। हेलीकॉप्टर अपेक्षाकृत कम ऊंचाई और कठिन इलाकों में भी उड़ान भर सकते हैं, जिससे दुश्मन के करीब जाकर ड्रोन तैनात करना आसान हो जाएगा। वहीं, मालवाहक विमानों से बड़े पैमाने पर ड्रोन छोड़ने की क्षमता 'स्वॉर्म अटैक' जैसी रणनीतियों को संभव बनाएगी, जिसमें एक साथ कई ड्रोन दुश्मन की रक्षा प्रणाली को भेदने का प्रयास करते हैं।

साहित्यिक और सामाजिक योगदान के लिए डॉ. मंजू लोढ़ा को लंदन में प्रतिष्ठित पुरस्कार

मुंबई। लंदन स्थित नेहरू सेंटर में आयोजित *"संवेदनाओं का सफ़र"* शीर्षक से साहित्यिक वार्ता एवं काव्य सत्र एक अविस्मरणीय और भावपूर्ण संध्या के रूप में सम्पन्न हुआ। इस कार्यक्रम में साहित्य, संवाद और संवेदनाओं का अद्भुत संगम देखने को मिला, जिसने उपस्थित सभी दर्शकों के हृदय को स्पर्श किया।इस गरिमापूर्ण आयोजन में श्री वीरेन्द्र शर्मा, लॉर्ड उदय नगराजु, डॉ. अनुराधा पांडेय, श्री कुलदीप शेखावत, मेयर प्रेरणा, रितु हिंदुजा जैसे अनेक प्रतिष्ठित अतिथियों की उपस्थिति रही। सभी गणमान्य अतिथियों ने लोढ़ा फाउंडेशन की अध्यक्षा तथा सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉ. मंजू मंगलप्रभात लोढ़ा के साहित्यिक योगदान और उनकी पुस्तकों पर अपने हृदयस्पर्शी विचार व्यक्त किये, जो उनके लिए अत्यंत भावुक और यादगार क्षण बन गये। समारोह का मुख्य आकर्षण सुप्रसिद्ध साहित्यकार तेजेंद्र शर्मा के साथ डॉ. मंजू लोढ़ा का संवाद रहा, जिसमें उन्होंने अपनी साहित्यिक यात्रा, जीवन के अनुभवों और अपनी लेखनी के पीछे की भावनाओं को साझा किया। इस अवसर पर उन्होंने अपनी दो नई पुस्तकों का प्रीव्यू भी प्रस्तुत किया, जिन्हें दर्शकों से विशेष सराहना मिली। इंदु बारोट ने डॉ. मंजू लोढ़ा की पुस्तकों और काव्य पर अत्यंत सुंदर, गहन और सरस्वती वंदना सदृश भावों से परिपूर्ण अपने विचार प्रस्तुत किए, जिसने कार्यक्रम की गरिमा को और भी ऊँचाई दी। कार्यक्रम की शुरुआत धृति बाफना द्वारा प्रस्तुत सरस्वती वंदना से हुई, जिसने पूरे वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। वहीं डॉ. अनीता नायर के प्रभावशाली और सुसंगठित संचालन ने पूरे आयोजन को सहज, गरिमामय और प्रवाहपूर्ण बनाए रखा। यह साहित्यिक संध्या प्रेम, प्रोत्साहन और शब्दों की शक्ति का एक सुंदर उत्सव रही, जिसने सभी को एक सूत्र में बांधते हुए हिंदी साहित्य को वैश्विक मंच पर नई ऊँचाई प्रदान की। अगले दिन आयोजित एक अन्य गरिमामय समारोह में डॉ. मंजू मंगलप्रभात लोढ़ा को उनके साहित्यिक योगदान एवं समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार *"IIW She Inspires Awards 2026"* से सम्मानित किया गया। यह प्रतिष्ठित सम्मान उनके निरंतर समर्पण, साहित्य सेवा और महिला सशक्तिकरण के प्रति उनके उल्लेखनीय योगदान का प्रतीक है, जिसने अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का गौरव और अधिक बढ़ाया।इस सम्मान समारोह का आयोजन रश्मि द्वारा किया गया।

विश्व धरोहर दिवस पर भावनगर मंडल में भव्य कार्यक्रम का आयोजन

विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल में हेरिटेज म्यूजियम, भावनगर परा में एक भव्य, सुव्यवस्थित एवं ज्ञानवर्धक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा के मार्गदर्शन तथा वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर एवं हेरिटेज अधिकारी श्री संतोष मिश्रा के नेतृत्व में यांत्रिक विभाग द्वारा आयोजित किया गया।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती शालिनी वर्मा, अध्यक्षा, पश्चिम रेलवे महिला कल्याण संगठन, भावनगर मंडल थीं। इस अवसर पर संगठन की महिला पदाधिकारी एवं सदस्याएँ भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहीं।

कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि एवं अन्य गणमान्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। वर्ष 2026 की थीम "संघर्ष एवं आपदाओं की परिस्थितियों में जीवित धरोहर के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया" के अनुरूप आयोजन में धरोहर संरक्षण के प्रति जागरूकता, उत्तरदायित्व एवं जनसहभागिता पर विशेष बल दिया गया।

अपने संबोधन में मुख्य अतिथि श्रीमती शालिनी वर्मा ने कहा कि सांस्कृतिक एवं तकनीकी धरोहरें केवल अतीत की स्मृति नहीं, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा, ज्ञान एवं पहचान का आधार हैं। उन्होंने आपदा एवं संकट की परिस्थितियों में धरोहरों के संरक्षण हेतु त्वरित एवं प्रभावी उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को धरोहर के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु शपथ दिलाई।

कार्यक्रम में केन्द्रीय विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विद्यार्थियों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विश्व धरोहर दिवस की थीम पर वक्तृत्व प्रतियोगिता एवं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वक्तृत्व प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 3 विद्यार्थियों तथा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में 10 विजेताओं को मुख्य अतिथि द्वारा पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर उपस्थित सभी प्रतिभागियों द्वारा हेरिटेज म्यूजियम, भावनगर परा का अवलोकन भी किया गया। भ्रमण के दौरान संग्रहालय में प्रदर्शित ऐतिहासिक लोकोमोटिव, कोच एवं अन्य धरोहर वस्तुओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर भारतीय रेल की समृद्ध विरासत को निकट से समझा गया।

कार्यक्रम का संचालन सहायक मंडल यांत्रिक अभियंता श्री विजय भट्ट द्वारा किया गया। अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। यह आयोजन न केवल ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक रहा, बल्कि धरोहर संरक्षण के प्रति जागरूकता एवं जिम्मेदारी की भावना विकसित करने में भी अत्यंत सफल सिद्ध हुआ।

पश्चिम रेलवे चलाएगी वटवा हावड़ा-वटवा समर स्पेशल ट्रेन

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की मांग एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए ट्रेन संख्या 09479/09480 वटवा–हावड़ा–वटवा समर स्पेशल ट्रेन को विशेष किराये पर चलाने का निर्णय लिया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है:

ट्रेन संख्या 09479 वटवा–हावड़ा समर स्पेशल ट्रेन दिनांक 20 अप्रैल 2026 एवं 26 अप्रैल 2026 को वटवा से 16:45 बजे प्रस्थान कर तीसरे दिन 09:00 बजे हावड़ा पहुंचेगी।

इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09480 हावड़ा–वटवा समर स्पेशल ट्रेन दिनांक 22 अप्रैल 2026 एवं 28 अप्रैल 2026 को हावड़ा से 19:00 बजे प्रस्थान कर तीसरे दिन 12:15 बजे वटवा पहुंचेगी। मार्ग में दोनों दिशाओं में यह ट्रेन वडोदरा जंक्शन, भरूच जंक्शन, अंकलेश्वर जंक्शन, उधना जंक्शन, नंदुरबार, भुसावल जंक्शन, खंडवा जंक्शन, इटारसी जंक्शन, जबलपुर, कटनी, सतना, मानिकपुर जंक्शन, प्रयागराज छिवकी, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, सासाराम, गया जंक्शन, कोडरमा, धनबाद जंक्शन तथा आसनसोल स्टेशनों पर ठहरेगी। इस ट्रेन में एसी 1-टियर एसी, 2-टियर एसी, 3-टियर एसी, स्लीपर तथा सामान्य श्रेणी के कोच रहेंगे।

ट्रेन संख्या 09479 वटवा–हावड़ा समर स्पेशल के लिए बुकिंग दिनांक 19 अप्रैल 2026 से सभी PRS काउंटर्स एवं IRCTC वेबसाईट पर उपलब्ध होगी।

पश्चिम रेलवे द्वारा साबरमती–आसनसोल समर स्पेशल ट्रेन का संचालन

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की मांग एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए ट्रेन संख्या 09431/09432 साबरमती–आसनसोल–साबरमती समर स्पेशल ट्रेन (विशेष किराये पर) चलाने का निर्णय लिया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है:

ट्रेन संख्या 09431 साबरमती–आसनसोल समर स्पेशल ट्रेन दिनांक 20 अप्रैल 2026 एवं 26 अप्रैल 2026 को साबरमती से 22:55 बजे प्रस्थान कर तीसरे दिन 13:15 बजे आसनसोल पहुंचेगी।

इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09432 आसनसोल–साबरमती समर स्पेशल ट्रेन दिनांक 22 अप्रैल 2026 एवं 28 अप्रैल 2026 को आसनसोल से 16:20 बजे प्रस्थान कर तीसरे दिन 07:15 बजे साबरमती पहुंचेगी।

मार्ग में दोनों दिशाओं में यह ट्रेन महेसाणा, पालनपुर, आबू रोड, फालना, मारवाड़ जंक्शन, ब्यावर, अजमेर, जयपुर, बांदीकुई, भरतपुर, अछनेरा, इडगाह आगरा, टुंडला, गोविंदपुरी, प्रयागराज जंक्शन, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, सासाराम, गया जंक्शन, कोडरमा तथा धनबाद स्टेशनों पर ठहरेगी। इस ट्रेन में स्लीपर एवं सामान्य श्रेणी के कोच उपलब्ध होंगे।

पश्चिम रेलवे विभिन्न गंतव्यों के लिए चलाएगी 05 जोड़ी ग्रीष्मकालीन स्पेशल ट्रेनें

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान उनकी यात्रा मांग को पूरा करने के उद्देश्य से विभिन्न गंतव्यों के लिए विशेष किराये पर 05 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इन ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार है:

1. ट्रेन संख्या 09087/09088 मुंबई सेंट्रल – अहमदाबाद एसी सुपरफास्ट साप्ताहिक स्पेशल [12 फेरे]

▶▶ट्रेन संख्या 09087 मुंबई सेंट्रल – अहमदाबाद स्पेशल प्रत्येक बुधवार को 23:20 बजे मुंबई सेंट्रल से प्रस्थान कर अगले दिन 07:20 बजे अहमदाबाद पहुंचेगी। यह ट्रेन 22 अप्रैल से 27 मई, 2026 तक चलेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09088 अहमदाबाद – मुंबई सेंट्रल स्पेशल प्रत्येक गुरुवार को 22:40 बजे अहमदाबाद से प्रस्थान कर अगले दिन 07:10 बजे मुंबई सेंट्रल पहुंचेगी। यह ट्रेन 23 अप्रैल से 28 मई, 2026 तक चलेगी।

▶▶यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, वापी, सूरत एवं वडोदरा स्टेशनों पर ठहरेगी।

▶▶इस ट्रेन में प्रथम एसी, एसी 2-टियर एवं एसी 3-टियर कोच होंगे।

2. ट्रेन संख्या 09085/09086 मुंबई सेंट्रल – इंदौर एसी सुपरफास्ट द्वि-साप्ताहिक स्पेशल [24 फेरे]

▶▶ट्रेन संख्या 09085 मुंबई सेंट्रल – इंदौर स्पेशल प्रत्येक सोमवार एवं शुक्रवार को 23:20 बजे मुंबई सेंट्रल से प्रस्थान कर अगले दिन 13:00 बजे इंदौर पहुंचेगी। यह ट्रेन 20 अप्रैल से 29 मई, 2026 तक चलेगी।

▶▶इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09086 इंदौर – मुंबई सेंट्रल स्पेशल प्रत्येक मंगलवार एवं शनिवार को 17:00 बजे इंदौर से प्रस्थान कर अगले दिन 07:10 बजे मुंबई सेंट्रल पहुंचेगी। यह ट्रेन 21 अप्रैल से 30 मई, 2026 तक चलेगी।

▶▶यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, वापी, सूरत, वडोदरा, दाहोद, रतलाम एवं उज्जैन स्टेशनों पर ठहरेगी।

▶▶इस ट्रेन में प्रथम एसी, एसी 2-टियर एवं एसी 3-टियर कोच होंगे।

3. ट्रेन संख्या 09053/09054 उधना – सांतरागाछी स्पेशल [04 फेरे]

▶▶ट्रेन संख्या 09053 उधना – सांतरागाछी स्पेशल सोमवार, 20 अप्रैल, 2026 एवं शनिवार, 25 अप्रैल, 2026 को 11:25 बजे उधना से प्रस्थान कर अगले दिन 21:00 बजे सांतरागाछी पहुंचेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09054 सांतरागाछी – उधना स्पेशल बुधवार, 22 अप्रैल, 2026 एवं सोमवार, 27 अप्रैल, 2026 को 00:05 बजे सांतरागाछी से प्रस्थान कर अगले दिन 10:00 बजे उधना पहुंचेगी।

▶▶यह ट्रेन दोनों दिशाओं में नंदुरबार, भुसावल, बडनेरा, नागपुर, गोंदिया, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, झारसुगुड़ा, राउरकेला, चक्रधरपुर, टाटानगर एवं खड़गपुर स्टेशनों पर ठहरेगी।

▶▶इस ट्रेन में स्लीपर एवं जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।

4. ट्रेन संख्या 09061/09062 उधना – जयनगर अनारक्षित स्पेशल [02 फेरे]

▶▶ट्रेन संख्या 09061 उधना – जयनगर स्पेशल रविवार, 19 अप्रैल, 2026 को 01:30 बजे उधना से प्रस्थान कर अगले दिन 13:50 बजे जयनगर पहुंचेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09062 जयनगर – उधना स्पेशल सोमवार, 20 अप्रैल, 2026 को 15:05 बजे जयनगर से प्रस्थान कर अगले दिन 06:15 बजे उधना पहुंचेगी।

▶▶यह ट्रेन दोनों दिशाओं में चलथान, बारडोली, नंदुरबार, भुसावल, खंडवा, इटारसी, जबलपुर, कटनी, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छेओकी, पं. दीनदयाल उपाध्याय, दिलदारनगर, बक्सर, आरा, दानापुर, पटना, बख्तियारपुर, मोकामा, बरौनी, समस्तीपुर, दरभंगा, सकरी एवं मधुबनी स्टेशनों पर ठहरेगी।

▶▶इस ट्रेन में जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।

5. ट्रेन संख्या 09067/09068 उधना – मधुबनी अनारक्षित स्पेशल [02 फेरे]

▶▶ट्रेन संख्या 09067 उधना – मधुबनी स्पेशल रविवार, 19 अप्रैल, 2026 को 05:30 बजे उधना से प्रस्थान कर अगले दिन 19:00 बजे मधुबनी पहुंचेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09068 मधुबनी – उधना स्पेशल सोमवार, 20 अप्रैल, 2026 को 20:00 बजे मधुबनी से प्रस्थान कर बुधवार को 09:35 बजे उधना पहुंचेगी।

▶▶यह ट्रेन दोनों दिशाओं में चलथान, बारडोली, नंदुरबार, भुसावल, खंडवा, इटारसी, पिपरिया, नरसिंहपुर, मदन महल, कटनी, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छेवकी, पं. दीनदयाल उपाध्याय, बक्सर, आरा, दानापुर, पटना, फतुहा, बख्तियारपुर, मोकामा, बरौनी, समस्तीपुर, दरभंगा एवं सकरी स्टेशनों पर ठहरेगी।

▶▶इस ट्रेन में जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।

▶▶ट्रेन संख्या 09053 की बुकिंग प्रारंभ है, जबकि ट्रेन संख्या 09087, 09088, 09085 एवं 09086 की बुकिंग 19.04.2026 से सभी पीआरएस काउंटरों तथा आईआरसीटीसी वेबसाइट पर प्रारंभ होगी। ट्रेनों के समय, ठहराव एवं संरचना संबंधी विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

सूरत में जल संकट की दस्तक: 20 अप्रैल को रांदेर अडाजन में कई घंटों तक बंद रहेगी पानी सप्लाई

सूरत। गुजरात के प्रमुख औद्योगिक शहर सूरत में एक बार फिर पानी की सप्लाई को लेकर बड़ी असुविधा की स्थिति बनने जा रही है। शहर के रांदेर और अडाजन क्षेत्र में रहने वाले हजारों परिवारों को 20 अप्रैल 2026, सोमवार की शाम को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा जरूरी तकनीकी कार्य के चलते कुछ घंटों के लिए जल आपूर्ति पूरी तरह बंद रखने का निर्णय लिया गया है। यह कदम भले ही अस्थायी असुविधा पैदा करेगा, लेकिन नगर निगम के अनुसार इसका उद्देश्य भविष्य में पानी की सप्लाई को और अधिक सुचारु और प्रभावी बनाना है।

नगर निगम के हाइड्रोलिक विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार रांदेर क्षेत्र के जोगनी नगर वॉटर डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन पर मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन का कार्य किया जाएगा। इस कार्य के तहत अडाजन स्थित स्टेशन से पानी के प्रेशर को बेहतर करने के लिए मुख्य कॉमन हेडर लाइन से जुड़े पाइपलाइन सिस्टम में नए वाल्व लगाए जाएंगे। इसके साथ ही टैंक को तेजी और संतुलित तरीके से भरने के लिए राइजिंग मेन लाइन को जोड़ा जाएगा, जिससे भविष्य में पानी की आपूर्ति अधिक स्थिर और नियंत्रित हो सकेगी। तकनीकी रूप से यह एक महत्वपूर्ण सुधार कार्य है, लेकिन इसके चलते फिलहाल आम लोगों को असुविधा झेलनी पड़ेगी।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 20 अप्रैल की शाम 5:30 बजे से रात 8:50 बजे तक पानी की सप्लाई पूरी तरह बंद रहेगी। हालांकि यह समय सीमा करीब साढ़े तीन घंटे की है, लेकिन नगर निगम ने यह भी स्पष्ट किया है कि कुछ इलाकों में पानी का प्रेशर पहले से ही कम हो सकता है और सप्लाई सामान्य होने में थोड़ा अतिरिक्त समय भी लग सकता है। यानी असर केवल निर्धारित समय तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उससे पहले और बाद में भी लोगों को पानी की कमी महसूस हो सकती है। इस जल कटौती का असर रांदेर और अडाजन क्षेत्र की बड़ी संख्या में सोसाइटियों और रिहायशी इलाकों पर पड़ेगा। जिन क्षेत्रों में पानी की सप्लाई बाधित रहने वाली है, उनमें मेरुलक्ष्मी सोसाइटी, रंगअवधूत सोसाइटी सेक्शन-3, गुजरात हाउसिंग बोर्ड, सुमन संध्या आवास, हयात रेजीडेंसी, रॉयल हेरिटेज, कॉजवे के आसपास की सोसाइटियां, शाश्वत कॉम्प्लेक्स, गोविंदनगर, सहजधाम, वसंत विहार, परशुराम गार्डन, एल.पी. सवाणी स्कूल क्षेत्र, सुमन विहार, मिलन पार्क, ग्रीन वैली, शुभम पार्क, यमुना कॉम्प्लेक्स, महर्षि अरविंदो सोसाइटी, जलाराम नगर, क्रिस्टल कॉम्प्लेक्स, अक्षरधाम सोसाइटी, डी-मार्ट क्षेत्र, हरिदर्शन सोसाइटी, उमिया पार्क, आत्मा पार्क, साईं विहार, आशानगर, संस्कार पार्क, हरिओम नगर, श्रीनाथ सोसाइटी, रेवानगर, नवरंग सोसाइटी, कंकूनगर, वेस्टर्न विला, ग्रीन एवेन्यू, टीजीबी रेस्टोरेंट के आसपास के इलाके और कई अन्य आवासीय क्षेत्र शामिल हैं। इसके अलावा रांदेर गामताल और आसपास के क्षेत्रों में भी पानी की सप्लाई बाधित होने या कम प्रेशर की समस्या सामने आ सकती है।

नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस अस्थायी स्थिति को ध्यान में रखते हुए पहले से ही आवश्यक पानी का संग्रह कर लें। खासतौर पर पीने के पानी, खाना बनाने और अन्य जरूरी घरेलू कार्यों के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी सुरक्षित रखने की सलाह दी गई है। साथ ही यह भी कहा गया है कि जल आपूर्ति बहाल होने के बाद भी कुछ समय तक पानी का उपयोग सावधानीपूर्वक और संयम से करें, ताकि सभी लोगों तक समान रूप से पानी पहुंच सके।